मंगलवार, 19 मई 2026

मौसम

तापमान 29 – 36
आर्द्रता 94%
सूर्योदय: 04:55 सूर्यास्त: 18:10

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

Epaper.samagya.in

समाज्ञा

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तृतीया, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : जिंदगी हमें गारंटी, वारंटी नहीं देती, सिर्फ हमें मौके देती हैं।

भारतीय मूल के आरोन राय ने तीन शॉट से पीजीए चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास पृष्ठ 8

टीएमसी शासन में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार की जांच के लिए दो समितियां गठित : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

रिटायर्ड जज करेंगे नेतृत्व, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी

■ दोनों समितियां एक जून से काम करना शुरू करेंगी

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में दो अलग-अलग समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने अपनी सहमति दे दी है और समिति एक जून से काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फैसले चुनाव प्रचार के दौरान किये गए वादे से जुड़े हैं और जनहित में किये गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाली समिति की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु करेंगे, वहीं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एडीजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी जयरमन इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि यह समिति केंद्रीय और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों और सेवा वितरण प्रणालियों में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। अधिकारी ने कहा कि यह समिति भ्रष्टाचार, 'कट मनी' (कमीशन), रिश्वतखोरी, सरकारी धन के गबन और उन मामलों की जाँच करेगी, जहां आम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, बिचौलिए, ठेकेदार, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और सहकारी निकाय-ये सभी इसके दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि आम लोग और सार्वजनिक कार्यों में शामिल एजेंसियां शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, और काम शुरू होने के 30 दिनों के भीतर सिफारिशें मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कार्रवाई की जाएगी। हम गबन किए गए सरकारी धन की वसूली करने का भी प्रयास करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी की अध्यक्षता वाली समिति महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं की जांच करेगी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन इसकी सदस्य-सचिव होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों समितियां एक जून से काम करना शुरू करेंगी। अधिकारी ने कहा कि आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक आयोग जैसे निकायों की लंबित सिफारिशों की भी जांच करेगा और जहां आवश्यक हो, मामलों को फिर से खोलने, नयी प्राथमिकी और पूरक आरोपपत्र दर्ज करने तथा कड़े अभियोजन उपायों की सिफारिश कर सकता है।

पुलिस कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं... मुख्यमंत्री की चेतावनी, कहा

'कश्मीर की तरह कोलकाता में भी थमेगा पत्थरबाजी का दौर'

मुख्यमंत्री ने पार्क सर्कस हिंसा में घायल पुलिस अधिकारियों का जाना हाल, की बैठक

हिंसा में छह पुलिस कर्मी और सीआरपीएफ के दो जवान घायल, 40 गिरफ्तार

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमला, तोड़फोड़ और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा हुईं तो सरकार बेहद सख्त कदम उठाएगी।पार्क सर्कस स्थित उपायुक्त कार्यालय का दौरा करने और घायल पुलिसकर्मियों तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि हिंसा की घटनाओं में छह पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के दो जवान घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की निगरानी स्वयं पुलिस आयुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में जारी नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस और केंद्रीय बलों की सराहना करते हुए कहा कि उकसावे और पथराव के बावजूद जवानों ने संयम बनाए रखा और बड़ी घटना को टाल दिया।शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ पुलिस बल के साथ खड़ी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत निडर होकर काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह सोच गलत है कि पुलिस बंधे हाथ-पैरों के साथ काम करेगी। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पथराव की घटनाओं की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा कि जैसे वहां पुलिस पर पत्थरबाजी बंद हुई है, वैसे ही पश्चिम बंगाल और कोलकाता में भी इसे समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और धार्मिक संगठन प्रशासन को सूचित कर कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक नारेबाजी और हिंसा को अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हिंसा को सुनियोजित बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से पूर्व नियोजित साजिश के संकेत मिले हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, इसे आखिरी चेतावनी समझें, अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लगाया 'जनता दरबार'

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपना पहला जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने जन शिकायतें और लोगों की मांगों को सुना। इसका आयोजन साल्टलेक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में किया गया। इस जनसंपर्क पहल का उद्देश्य लोगों की सीधी पहुंच पर केंद्रित शासन का संकेत देना है। कार्यक्रम की घोषणा भाजपा द्वारा सुबह लगभग 9 बजे अचानक की गई और मुख्यमंत्री 45 मिनट के भीतर पार्टी कार्यालय पहुंच गए। जनता दरबार की अवधि लगभग एक घंटे की थी। छात्रों और स्थानीय लोगों सहित कई लोगों ने इसमें भाग लिया और मुख्यमंत्री से एक-एक कर बंद कमरे में बातचीत की, जिसमें स्थानीय मुद्दों से लेकर सिंडिकेट से संबंधित दबाव के आरोपों तक की शिकायतें की गईं। इस जन संवाद में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और शशि अग्निहोत्री भी उपस्थित थीं। जनता दरबार के आयोजन स्थल के बाहर, उपस्थित कुछ लोगों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा उनकी शिकायतें सुने जाने से उन्हें राहत मिली है। हालांकि, भाजपा ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कार्यक्रम के आगामी संस्करण कहां आयोजित किए जाएंगे, लेकिन पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि यह पहल नयी सरकार की जनसंपर्क रणनीति का एक नियमित हिस्सा बन सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

ओस्लो : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। मोदी को यह सम्मान भारत-नॉर्वे संबंधों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान और उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' प्रदान किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, ''ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यह सम्मान भारत की जनता को समर्पित है और भारत तथा नॉर्वे के बीच अटूट मित्रता का प्रतीक है। यह वैश्विक प्रगति के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और नॉर्वे के लोगों के बीच स्नेह और सद्भावना का प्रतीक बताया। 'ग्रैंड क्रॉस' रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सर्वोच्च दर्जा है। यह सम्मान नॉर्वे के हितों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। एक दिन पहले मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया था। यह सम्मान विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन से दो-दिवसीय यात्रा पर ओस्लो पहुंचे थे। यह मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की भी नॉर्वे की यह पहली यात्रा है।

सीबीआई ने शुभेंदु के पीए की हत्या मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

परिवार संग हरिद्वार से लौट रहा था शूटर, अदालत से मिला 24 घंटे का रिमांड

नयी दिल्ली/कोलकाता : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रकांत रथ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे राजकुमार सिंह को सोमवार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सिंह को सीबीआई की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। बताया गया है कि आरोपी अपने परिवार के साथ हरिद्वार से वापस लौट रहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम पहले से ही टोल प्लाजा के पास तैनात थी। स्थानीय पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि जांच एजेंसी को पहले से ही आरोपी की गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी थी। इसके बाद टीम ने छपार टोल प्लाजा के आसपास घेराबंदी कर दी। सोमवार के तड़के जैसे ही आरोपी की गाड़ी टोल के पास पहुंची, केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से काफी देर तक पूछताछ की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी आरोपी को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंची। अदालत से आरोपी का 24 घंटे का पारगमन रिमांड प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी अब आरोपी से पूछताछ कर हत्या की साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद मामले में कई नए खुलासे हो सकते हैं।

RED-X
B.W.P. PLY,
BOARDS& DOORS
'X' Factor that Makes A Difference
Stockist :
GULAB CHAND
LAL CHAND& Co.
9831114555
9874415555

शिफ्ट में पढ़िए नमाज, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं : योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नमाजियों से कहा कि नमाज पढ़नी आवश्यक है तो शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। योगी ने बकरीद पर्व से पहले कहा, ''हम सड़कों पर अराजकता नहीं पलने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।'' मुस्लिम समुदाय का प्रमुख पर्व बकरीद संभवत: इस महीने की 28 तारीख को मनाया जायेगा। मुख्यमंत्री एक प्रमुख समाचार पत्र के स्थापना दिवस पर आज लखनऊ में आयोजित ''संवाद उत्तर प्रदेश: स्वर्ण शताब्दी की ओर' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ''बाहर लोग पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती, मैं कहता हूं कि कतई नहीं होती। जाकर देख लीजिए, नहीं होती है।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि ''सड़कें चलने के लिए हैं, या कोई भी व्यक्ति आकर चौराहे पर तमाशा बना देगा। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का और आवागमन बाधित करने का उसको कौन सा अधिकार है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि ''जहां उसका स्थल होगा वहां जाकर पढ़े। उन लोगों ने कहा कि कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, क्या करें, तो हमने कहा कि शिफ्ट में पढ़ लो। नमाज पढ़नी आवश्यक है तो आप शिफ्ट में पढ़िये। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे।'' उन्होंने फिर दोहराया, ''सड़क चलने के लिए है, आम नागरिक के लिए है, बीमार व्यक्ति के लिए है, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है।'' योगी ने कहा कि ''हम अराजकता सड़कों पर नहीं पलने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।

स्क्वाड्रन लीडर सान्या श्रेणी-ए क्यूएफआई योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं: वायु सेना

नयी दिल्ली : भारतीय वायु सेना ने सोमवार को कहा कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या ने प्रतिष्ठित श्रेणी-ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक (क्यूएफआई) योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। भारतीय वायु सेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह भारतीय वायु सेना के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है और पूरे देश में महत्वाकांक्षी विमान चालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के सान्या को सम्मानित करने की तस्वीरें भी पोस्ट में साझा की गईं। पोस्ट में कहा गया, ''स्क्वाड्रन लीडर सान्या ने प्रतिष्ठित श्रेणी-ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक (क्यूएफआई) योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उनकी यह उपलब्धि समर्पण और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रतीक है।'' पोस्ट में कहा गया, ''यह भारतीय वायु सेना के लिए गर्व का पल है और देशभर में विमानन क्षेत्र में करियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।''

रुपया 39 पैसे टूटकर 96.20 प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर

मुंबई : रुपया सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 58 पैसे टूटने के बाद कारोबार के अंत में 39 पैसे की गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर 96.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, जारी भू-राजनीतिक तनाव और मजबूत डॉलर के कारण रुपये पर दबाव रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से वैश्विक बाजार धारणा प्रभावित बनी हुई है। इसके अलावा भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का दबाव बना हुआ है, क्योंकि ऊंची दरों के कारण डॉलर की बाजार से निकासी बढ़ जाता है। कारोबारियों ने बताया कि एफपीआई के कारण पहले से ही धन निकासी हो रही है।

लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा

10 लोगों की मौत

मैजिक वैन और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने जताया शोक

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में चालक समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा ईसानगर थाना क्षेत्र में सिसैया-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर हुआ, जहां एक मैजिक वैन और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। पुलिस के अनुसार, वैन लखीमपुर से बहराइच जा रही थी और उसमें चालक सहित 10 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन में बैठे सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि वैन अपनी लेन से हटकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नौ मृतकों की पहचान कर ली है, जबकि एक शव की पहचान का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे को हृदय विदारक बताते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

संवेदनशील विषयों पर अभिव्यक्ति में सतर्कता जरूरी

इसमें दो राय नहीं कि देश के प्रतिष्ठित व शीर्ष पदों पर विराजमान व्यक्तियों को अपने संस्थानों व सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखने में अतिरेक में सावधानी बरतनी चाहिए। उससे निकलने वाले शब्दों के अर्थों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसी ही चर्चा देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के हालिया बयानों को लेकर हुई। बताया जाता है कि एक अधिवक्ता द्वारा सीनियर का दर्जा दिए जाने के बाबत दायर याचिका पर खिन्न मुख्य न्यायाधीश ने प्रासंगिक संदर्भ में जो कहा, उसको लेकर सवाल उठे। बताया जा रहा है कि 'उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि समाज में पहले से ऐसे परजीवी हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं... कुछ युवा ऐसे हैं, जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण 'कॉकरोच' की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उसमें से कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं।' निश्चय ही हाल के वर्षों में संपादक विहीन सोशल मीडिया में लोगों के अराजक व्यवहार को देखते हुए यह भले ही यह सत्य न हो, कुछ लोग इसे अर्धसत्य बताते हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से इस विषय पर संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने 'कॉकरोच' वाले बयान पर कहा है कि 'मीडिया ने उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश किया।' उन्होंने अपनी मौखिक टिप्पणी के बाबत कहा कि उनकी बातों को इस तरह पेश किया गया जैसे उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। उनका कथन था कि उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों के खिलाफ थीं, जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घुस आए हैं, इसलिए परजीवियों की तरह हैं। उनका इशारा न्यायापालिका पर होने वाले अनुचित हमलों की तरफ था। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की कानून की डिग्रियों की जांच प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा डाली जाने वाली सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानूनी डिग्रियों की प्रमाणिकता पर संदेह है। लेकिन इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों व सोशल एक्टिविस्ट ने सीजेआई की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी हैं। राज्यसभा में एक राजद सांसद ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्य न्यायाधीश की भाषा को लेकर चिंता जतायी। उनका कहना था कि बेरोजगारों, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना 'कॉकरोच' व 'परजीवी' से करना लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने वाला लगता है। आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वह संवैधानिक संयम व गरिमा की अंतिम शरणस्थली बनी रहे। एक आरटीआई कार्यकर्ता का मानना है कि प्रश्न पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, ये व्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाये रखने में भूमिका है।

कैसे एक राज्यपाल ने बंगाल के चुनावी विमर्श को दिया नया रूप

डा. सीवी आनंद बोस
पूर्व राज्यपाल, पश्चिम बंगाल

- डॉ. सीवी आनंद बोस ने राज्यपाल पद पर रहते बंगाल की राजनीति में जवाबदेही की नई बहस खड़ी की
- जब राजभवन बना जनविश्वास का केंद्र
- सीमित अधिकारों के बावजूद राजभवन की दृश्यमान भूमिका ने शासन को लेकर जनता की अपेक्षाओं को नई दिशा दी

हाल में राज्य में नई भाजपा सरकार के गठन से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में एक अनोखा दौर देखा। एक ओर राज्य की निर्वाचित सरकार थी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पिछले लगातार 15 वर्षों से कर रही थीं। दूसरी ओर संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए राजभवन था, जिसका नेतृत्व नवंबर 2022 से तत्कालीन राज्यपाल डा. सीवी आनंद बोस कर रहे थे। संविधान के तहत राज्यपाल के अधिकार सीमित होते हैं। उनके पास न तो कोई राजनीतिक संगठन होता है, न सरकारी योजनाओं का सीधा संचालन, और न ही चुनावी तंत्र। इसके बावजूद, बंगाल के हालिया राजनीतिक विमर्श में राजभवन की सक्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी रही।

विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल बोस की कार्यशैली ने शासन और जवाबदेही को लेकर जनता के बीच एक अलग प्रकार की बहस को जन्म दिया। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक निष्क्रियता और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों के बीच राजभवन की सक्रिय उपस्थिति ने लोगों को यह संकेत दिया कि संवैधानिक संस्थाएँ भी आम नागरिकों की शिकायतों को सुन सकती हैं।

तीन वर्षों में बनी एक अलग प्रशासनिक छवि

पहला चरण – जनता तक पहुँच : 2023 में राज्य में पंचायत चुनावों के बाद हिंसा की व्यापक घटनाओं के बीच राज्यपाल बोस ने विभिन्न जिलों का दौरा किया। राजभवन में शिकायत सुनने की व्यवस्था बनाई गई और कई मामलों में प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई। इससे आम नागरिकों के बीच यह संदेश गया कि संवैधानिक संस्थाएँ केवल औपचारिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि संवाद का माध्यम भी बन सकती हैं।

दूसरा चरण – जवाबदेही पर जोर : संदेशखाली प्रकरण, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर विवाद और भर्ती घोटालों जैसे मुद्दों पर राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से पारदर्शिता और नियमों के पालन की बात उठाई। कुलाधिपति के रूप में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रक्रियागत शुचिता पर बल दिया। इससे शासन व्यवस्था में जवाबदेही की चर्चा और तेज हुई।

तीसरा चरण – संतुलित सक्रियता : चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था, केंद्रीय बलों की तैनाती और विभिन्न सामाजिक समूहों से संवाद जैसे मुद्दों पर राजभवन लगातार सक्रिय दिखाई दिया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि सार्वजनिक मतभेदों के बावजूद मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति संवैधानिक शिष्टाचार बनाए रखा गया। यही संतुलन कई लोगों को आकर्षित करता दिखाई दिया- एक ओर सक्रियता, दूसरी ओर संस्थागत मर्यादा।

मतदाताओं के मानस पर प्रभाव

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस सक्रियता ने मतदाताओं के बीच एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किया। तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ पहले से मौजूद असंतोष- जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा- को लेकर लोगों में चर्चा थी। लेकिन जब शिकायतों पर कार्रवाई, जांच एजेंसियों की सक्रियता या प्रशासनिक प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी, तब शासन को लेकर अपेक्षाएं भी बदलीं।

इसी दौरान भाजपा ने डबल इंजन सरकार के अपने राजनीतिक संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। तर्क यह दिया गया कि यदि सीमित संवैधानिक अधिकारों के भीतर राजभवन सक्रिय भूमिका निभा सकता है, तो पूर्ण अधिकार वाली सरकार अधिक प्रभावी प्रशासन दे सकती है।

हालांकि यह भी स्पष्ट है कि चुनावी परिणाम केवल एक कारक से तय नहीं होते। सत्ता विरोधी माहौल, भाजपा का संगठनात्मक विस्तार, केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव और स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण रहे। राज्यपाल के रूप में बोस की भूमिका को कई विश्लेषक एक विश्वसनीयता बढ़ाने वाले तत्व के रूप में देखते हैं, न कि अकेले निर्णायक कारण के रूप में।

बंगाल में यह मॉडल क्यों चर्चा में आया

पश्चिम बंगाल लंबे समय से तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। ऐसे में कई मतदाता स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन चाहते थे। एक वर्ग के लिए राज्यपाल बोस की शैली अपेक्षाकृत शांत, प्रशासनिक और संस्थागत दिखाई दी। विशेष रूप से शिक्षित और शहरी मतदाताओं के बीच यह धारणा बनी कि राजनीतिक टकराव से अलग भी शासन और संवाद की भाषा संभव है।

संवैधानिक संतुलन की आवश्यकता

लोकतंत्र में सक्रिय संस्थाएं हमेशा सकारात्मक मानी जाती हैं, लेकिन इसके साथ संवैधानिक सीमाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। भारत का संघीय ढाँचा राज्य सरकारों और राज्यपाल दोनों की भूमिकाओं के संतुलन पर आधारित है। इसलिए यह बहस भी सामने आई कि राज्यपाल की सक्रियता संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहनी चाहिए और उसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रत्यक्ष माध्यम नहीं बनना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत सक्रियता तभी प्रभावी मानी जाएगी, जब वह निष्पक्षता और संयम के साथ हो।

राजभवन केवल एक औपचारिक संस्था भर नहीं रहा

पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक दौर में राजभवन केवल एक औपचारिक संस्था भर नहीं रहा, बल्कि शासन, जवाबदेही और संवैधानिक सक्रियता पर चर्चा का केंद्र बन गया। पूर्व राज्यपाल डा. सीवी आनंद बोस की कार्यशैली ने यह संदेश दिया कि संवैधानिक पदों की सक्रिय उपस्थिति जनता के बीच भरोसा पैदा कर सकती है। अंततः चुनावी निर्णय जनता ने कई राजनीतिक और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखकर लिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में राजभवन की भूमिका ने बंगाल की राजनीतिक बहस को नई दिशा देने में अपनी एक अलग पहचान बनाई।

ट्रंप की ताइवान से जुड़ी टिप्पणियों पर चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी

बीजिंग : बीजिंग की हालिया यात्रा के बाद ताइवान की स्वतंत्रता के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख से चीन प्रसन्न दिख रहा है। चीन की राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने 'फॉक्स न्यूज' को बताया कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई कहे कि 'चलो स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा समर्थन कर रहा है'।अमेरिकी नेता ताइवान के लिए 11 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी देने के बारे में भी अनिश्चित दिखे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को कहा कि बीजिंग ने ताइवान पर राष्ट्रपति ट्रंप की नवीनतम टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगने पर गुओ ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'ताइवान चीन के भूभाग का एक अविभाज्य हिस्सा है, यह कभी एक देश नहीं रहा है, और न ही भविष्य में कभी होगा।' उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों से समर्थन मांगकर स्वतंत्रता प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं होता और राष्ट्रीय एकीकरण ही उज्ज्वल भविष्य का एकमात्र मार्ग है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे को ठीक से न संभालने से दोनों देशों के बीच 'टकराव और यहां तक कि संघर्ष' भी शुरू हो सकता है।

चीन-अमेरिका की निकटता से भारत के सामने वैश्विक चुनौतियाँ

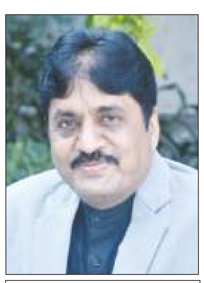

ललित गर्ग

दुनिया एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ दो महाशक्तियों– अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संवाद, आपसी मुलाकातों और कूटनीतिक समीकरणों को केवल द्विपक्षीय संबंधों के रूप में नहीं देखा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संवाद और संभावित समझौतों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक वर्ग इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए राहतकारी कदम मान रहा है, क्योंकि इससे बढ़ती महंगाई, व्यापारिक अवरोधों और युद्धजन्य संकटों में कमी आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निकटता भविष्य में एक ऐसे विश्व संरचना को जन्म दे सकती है जहाँ दुनिया की दिशा पुनः कुछ महाशक्तियों के हाथों में सिमट जाए और विकासशील तथा अर्धविकसित देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ। भारत जैसे देशों के लिए यह परिस्थिति अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है।

आज अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार, तकनीकी विकास, ऊर्जा बाजार, वैश्विक निवेश, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों पर इन दोनों देशों का गहरा प्रभाव है। ऐसे में इनके संबंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, टैरिफ विवाद, तकनीकी प्रतिबंध और ताइवान से जुड़े तनावों ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाला। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ टूट गईं, रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा संकट बढ़ाया और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेला। इन परिस्थितियों में यदि अमेरिका और चीन संवाद और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बल मिल सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से सबसे पहले वैश्विक बाजारों को राहत मिलेगी। निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, तकनीक तथा विनिर्माण क्षेत्रों में लागत घट सकती है। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण संभव है। किंतु यह केवल तस्वीर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यदि दोनों महाशक्तियाँ वैश्विक व्यापारिक नियमों और आर्थिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार तय करने लगें तो छोटे देशों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दुनिया पहले भी उपनिवेशवाद और आर्थिक नियंत्रण की राजनीति देख चुकी है, अब आशंका यह है कि कहीं आर्थिक वैश्वीकरण का नया स्वरूप महाशक्तियों के संयुक्त वर्चस्व में परिवर्तित न हो जाए। इसी संदर्भ में जी-2 यानी अमेरिका और चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था की चर्चा तेज हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विश्व धीरे-धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था से हटकर दो महाशक्तियों के प्रभाव वाले ढाँचे की ओर बढ़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक नीतियों, व्यापारिक समझौतों और सुरक्षा संबंधी निर्णयों में छोटे देशों की भूमिका सीमित हो सकती है। यह स्थिति भारत जैसे देशों के लिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि भारत हमेशा से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सामूहिक वैश्विक नेतृत्व का समर्थक रहा है।

भारत की स्थिति यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिकी खेमे में है और न ही चीन के प्रभाव क्षेत्र में। भारत ने लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा, तकनीकी और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका है। दूसरी ओर चीन भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सीमा विवादों के बावजूद व्यापारिक संबंध व्यापक हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन का विषय है। भारत और चीन की तुलना करें तो चीन ने पिछले तीन दशकों में विनिर्माण, निर्यात, आधारभूत संरचना और तकनीकी उत्पादन के माध्यम से स्वयं को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया। चीन की आर्थिक नीति केंद्रीकृत और तीव्र निर्णय क्षमता वाली रही है। इसके विपरीत भारत का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था, विविधता और संस्थागत संतुलन पर आधारित रहा है। भारत की शक्ति उसकी युवा आबादी, लोकतंत्र, सेवा क्षेत्र और डिजिटल क्षमता में निहित है, जबकि चीन की शक्ति विनिर्माण, निर्यात और पूंजी निवेश में रही है। अमेरिका के साथ चीन के संबंधों में सुधार होने की स्थिति में भारत के सामने यह चुनौती होगी कि वह अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपयोगिता को और अधिक प्रभावशाली बनाए।

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर चाइना प्लस वन रणनीति में निहित है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले वर्षों में चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत, वियतनाम और अन्य देशों की ओर बढ़ी हैं। भारत यदि अपनी औद्योगिक नीतियों, आधारभूत संरचना, श्रम सुधार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करता है तो वह वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन सकता है। किंतु यदि भारत आवश्यक गति से सुधार नहीं कर पाया तो यह अवसर अन्य देशों के पास चला जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका-चीन संबंधों का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स नई शक्ति राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है जबकि चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत इन दोनों के बीच एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। भारत के पास प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा को वैश्विक नेतृत्व में बदलने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि चाहिए।

भू-राजनीतिक दृष्टि से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकटों पर अमेरिका और चीन की भूमिका निर्णायक है। यदि दोनों देशों के बीच समझ बढ़ती है तो सैन्य टकरावों की आशंका कम हो सकती है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होंगे और तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए यह अत्यंत लाभकारी स्थिति होगी। लेकिन यदि दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव विस्तार के लिए संकटों का उपयोग करती हैं तो विश्व अस्थिरता और बढ़ सकती है। भारत की विदेश नीति के लिए यह समय अत्यंत निर्णायक है। भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए चीन के साथ व्यावहारिक संबंधों का संतुलन बनाना होगा। साथ ही उसे वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की अवधारणा प्रस्तुत की थी, वह भविष्य की विश्व व्यवस्था का वैकल्पिक मॉडल बन सकती है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चीन जहाँ शक्ति संतुलन की राजनीति में उलझे हुए हैं, वहीं भारत सहअस्तित्व, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग की नीति पर चल रहा है। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है जबकि भारत का दृष्टिकोण विकास, मानवीय मूल्यों और वैश्विक साझेदारी पर केंद्रित रहा है। यही भारत की विशिष्टता और शक्ति है।

आज दुनिया में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि क्या अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया को पुनः अपने प्रभाव क्षेत्र में बाँटने का प्रयास करेंगे? क्या छोटे देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी? क्या फिर वही स्थिति बनेगी जब महाशक्तियाँ विश्व राजनीति को अपनी उँगलियों पर नचाती थीं? इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आज की दुनिया शीत युद्ध काल की दुनिया नहीं है। भारत, जापान, यूरोपीय संघ, ब्राजील, आसियान और अफ्रीकी देशों का बढ़ता प्रभाव विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय बनाए रखने में सक्षम है। भारत को इस बदलती परिस्थिति में अपने संकल्पों को सुदृढ़ करना होगा, विकास के नए मानक गढ़ने होंगे और अपनी रणनीतिक क्षमता को विस्तार देना होगा। क्योंकि बदलती दुनिया में प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और चीन क्या करेंगे, बल्कि यह है कि भारत स्वयं को किस ऊँचाई पर स्थापित करेगा।

–लेखक,पत्रकार एवं स्तंभकार

विदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के महाराजा से मुलाकात की

ओस्लो : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ओस्लो के शाही महल में नॉर्वे के महाराजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में तेजी से हो रहे बदलावों और नॉर्वे के व्यवसायों के लिए देश में उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नॉर्वे के महाराजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से हो रहे बदलावों और नॉर्वे के व्यवसायों तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार जैसे क्षेत्रों के भागीदारों के लिए देश में उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला। जायसवाल ने कहा, महाराजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोपहर के भोज की मेजबानी की। इससे पहले, मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को यह सम्मान भारत-नॉर्वे संबंधों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान तथा उनके दूरदर्शी नेतत्व के लिए दिया गया।

इजराइल, हिजबुल्ला के बीच संघर्ष में लेबनान में मरने वालों की संख्या तीन हजार हुई

बेरूत : लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला के बीच हुए संघर्ष में मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि युद्धविराम के बावजूद जारी संघर्ष की नयी घटनाओं में मरने वालों की संख्या अब तक 3,020 हो गई है, जिनमें 292 महिलाएं और 211 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के दो दिन बाद दो मार्च को हिजबुल्ला आतंकवादी समूह द्वारा इजराइल पर गोलीबारी के साथ लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और राजधानी बेरूत तथा अन्य क्षेत्रों पर बमबारी की।

आज का पंचांग

कोलकाता : 19 मई, मंगलवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2083, ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तृतीया, 14:22 तक, नक्षत्र : मृगशीर्षा, 08:41 तक, योग : धृति, 17:49 तक, सूर्योदय: 04:55, सूर्यास्त: 18:10, चन्द्रोदय : 07:39, चन्द्रास्त: 21:52, शक सम्वतः 1948 पराभव, सूर्य राशि : वृषभ, चन्द्र राशि : मिथुन, राहू काल : 15:27 से 17:05

राशिफल

मेष : आज लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए हर काम पूरे फोकस के साथ करें। बिजनेस की कोई अहम डील बीच में अटक सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा।

वृष : आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमाल दिखा सकती है, लेकिन बिना मांगी सलाह देने से बचना ही समझदारी होगी। शॉपिंग के दौरान खर्चों पर कंट्रोल रखें।

मिथुन : आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। यात्रा या घूमने के दौरान कोई खास जानकारी हाथ लग सकती है। रुके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे।

कर्क : आज जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। एक साथ कई काम आने से मन उलझन में रहेगा। पुरानी गलती से मिली सीख आज आपके बहुत काम आएगी।

सिंह : आज का दिन आपके लिए शानदार अवसर लेकर आ सकता है। यात्रा के दौरान कोई खास खबर या जानकारी मिल सकती है। पुरानी नौकरी से दोबारा ऑफर आने के संकेत हैं।

कन्या : आज का दिन आपके लिए खास और उत्साह से भरा रह सकता है। शेयर मार्केट में निवेश का विचार आएगा, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होगा।

तुला : आज सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छोटी परेशानी भी बड़ी लग सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी मेहनत करेंगे और सफलता के करीब पहुंचेंगे।

वृश्चिक : आज आपकी सकारात्मक सोच सफलता का रास्ता खोल सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप शानदार तरीके से निभाएंगे।

धनु : आज का दिन मिला-जुला असर लेकर आएगा। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। बड़े सपने आपकी मेहनत को नई दिशा देंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी सामने आ सकती हैं।

मकर : आज आपके दिमाग में बिजनेस और कमाई को लेकर शानदार आइडिया आ सकते हैं। सही समय पर उठाया गया कदम बड़ा फायदा दिला सकता है।

कुम्भ : आज गुस्से पर कंट्रोल रखना आपकी सबसे बड़ी जीत साबित होगा। परिवार वाले आपकी छोटी बातों से भी नाराज हो सकते हैं, इसलिए शांत रहना बेहतर रहेगा।

मीन : आज बेवजह के विवादों और झंझटों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। परिवार को दी गई जिम्मेदारियाँ लोग अच्छे से निभाएंगे, जिससे आपका भरोसा बढ़ेगा।

वर्ग पहेली नं. 3443

1			2	■	3		4		5
	■	■	6			■		■	
7	8			■	9		■	10	
■		■	11	12		■	13	■	
■	14		■		■	15		16	
17		■	18		19	■	20		■
	■	21	■	22		23		■	24
25			■		■		■	26	
	■	27		■	28				

बायें से दायें:- 1) छुट्टी, 3) ग़द्दारी, 6) मिस; कारण, 7) जल-पोत, 9) बाज़ी, 10) स्पष्ट, 11) गंध, 14) औषधियों को उबालकर निकाला गया रस, 15) ऊपरी (दृष्टि), 17) अलग, 18) विपत्ति, 20) पशुशाला; घेरा; सामनेवाला आँगन, 22) प्रसिद्ध, 25) मायका, 26) तिब्बती बौद्धगुरु, 27) चालाक; प्रचलित, 28) किसी कला में निपुण.

ऊपर से नीचे:- 1) i ơZ; बड़ा भाई, 2) ओस, 3) विनाशकारी, 4) जुड़ा; लगा, 5) पक्षपात, 8) चुनौती, 12) शपथपत्र, 13) अनेक बार, 16) गंदा; बदबूदार, 17) दुधमुँहा, 19) अंधेरा, 21) प्रश्नपत्र, 23) ज़रिया; सहायता, 24) पराकाष्ठा; चमत्कार, 26) मृत शरीर.
(उत्तर: अगले अंक में)

पिछली पहेली का उत्तर

म	■	स	भा	■	म	ग़	ज़	■	द
न	■	द	र	गा	ह	■	ना	म	र्द
मा	लु	मा	त	■	ज़	बा	नी	■	ना
ना	का	■	■	अ	■	ल	■	त	क
■	छि	ड़	क	ना	■	म	ग	र	■
प	पी	■	म	र	ना	■	ज़	ह	री
ज	■	■	र	■	मु	खा	■	■	झ
मा	रा	मा	री	■	सी	प	■	का	ना
■	ष्ट्र	■	न	हीं	■	त	रा	जू	■

Mob. No. 08329510310

सुडोकू-पहेली-3401

6		5		9	2			
				6				8
					4		1	
1	2				5			
	4		7	8				
			3		8			2
				1			4	7
	8			7				1

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

••••

आड़ी और खड़ी में एवं 3–3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3400 का उत्तर

4	8	9	5	6	3	7	1	2
6	3	1	2	4	7	8	9	5
2	5	7	1	8	9	6	4	3
3	1	2	8	9	6	5	7	4
9	4	5	3	7	2	1	8	6
8	7	6	4	1	5	2	3	9
5	9	4	7	2	1	3	6	8
7	2	8	6	3	4	9	5	1
1	6	3	9	5	8	4	2	7

दूसरे कैबिनेट बैठक में महिलाओं को एक जून से 3,000 रुपये प्रतिमाह एवं फ्री बस सेवा को मंजूरी

इमाम, मुअज्जिन और पुरोहितों के भत्ते बंद, धर्म आधारित योजनाएं समाप्त

हाई कोर्ट के आदेश पर ओबीसी सूची रद्द

सातवें वेतन आयोग को मंजूरी, डीए पर नहीं हुई चर्चा, वेतन ढांचे में होगा संशोधन

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों के लिए धार्मिक आधार पर जारी सहायता संबंधी योजनाएं इस वर्ष जून से बंद कर दी जाएंगी। राज्य की महिला, बाल एवं सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित योजनाओं को बंद करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि इस योजना के लिए मौजूदा राज्य बजटीय आवंटन भी रद्द किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के लिए चल रही किसी भी छात्रवृत्ति योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 'अन्नपूर्णा' योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत एक जून से उन्हें 3,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, राज्य द्वारा संचालित बसों में उनके मुफ्त यात्रा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मौजूदा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के आधार पर रद्द किए जाने की घोषणा की। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने, हालांकि, इसकी पुष्टि भी की कि राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का मुद्दा सोमवार की बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था।

पॉल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक जून से महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने वाली 'अन्नपूर्णा' योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जो लाभार्थी पहले की सरकार की 'लक्ष्मीर भंडार' योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे स्वतः ही 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। धनराशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही एक वेब पोर्टल शुरू करेगी ताकि जिन महिलाओं को अब तक यह सहायता नहीं मिली है, वे नए आ-वेदन कर सकें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर चुकी हैं और जिन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए न्यायाधिकरण में अपील की है, वे भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी। पॉल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक जून से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हालांकि, बसों के बेड़े में तत्काल विस्तार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका दायरा नगर निकायों, स्थानीय निकायों, शिक्षा बोर्ड और राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन का विवरण जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि, इसके लागू होने की तारीख स्पष्ट नहीं की गई।

मंत्रिमंडल के एक अन्य अहम निर्णय की घोषणा करते हुए पॉल ने कहा कि नई भाजपा सरकार राज्य की मौजूदा ओबीसी सूची को 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप रद्द करेगी।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य की ओबीसी सूची की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उस सूची में वर्गों के ऐसे वर्गीकरण तथा पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन सेवाओं और पदों में ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत को समाप्त किया जाएगा। यह निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 22 मई 2024 के फैसले के अनुसार लिया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य ओबीसी श्रेणी की पात्रता तय करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना क्रमांक ईएलडी-125-डब्ल्यूसी-ओटी-08-26, दिनांक 13.05.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (क.वि.), पूर्व रेलवे, हावड़ा, नई डीआरएम बिल्डिंग, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा निम्नवर्णित कार्यों के लिए निविदा क्रमांक **ईएलडी-125-डब्ल्यूसी-ओटी-08-26** के प्रतिपक्ष ई-निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम एवं स्थान :** पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में प्रांतिक स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के विस्तार के संबंध में 25 केवी ओएचई रूपांतरण। **कार्य की अनुमानित लागत :** रु. 17,45,729,40, **निविदा प्रपत्र की लागत :** शून्य। **बयाना राशि/बोली सुरक्षा जमा की जानी है:** रु. 34,900/-, **कार्य समाप्ति की अवधि :** एलओए जारी करने की तिथि से 12 (बारह) माह। **निविदा समापन तिथि और समय:** दिनांक 10.06.2026 को 15.00 बजे। **निविदा का खुलना:** निविदा के बंद होने के बाद किसी भी समय निविदा खोली जाएगी। निविदाकार निविदा के संपूर्ण विवरण/वर्णन/विनिर्देश के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देख सकते हैं एवं अपनी बोली ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं कोई मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

HWH-72/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना क्रमांक ईएलडी-125-डब्ल्यूसी-ओटी-12-26, दिनांक 13.05.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (क.वि.), पूर्व रेलवे, हावड़ा, नई डीआरएम बिल्डिंग, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा निम्नवर्णित कार्यों के लिए निविदा क्रमांक **ईएलडी-125-डब्ल्यूसी-ओटी-12-26** के प्रतिपक्ष ई-निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम एवं स्थान :** पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में मुरारी एवं गुमानी स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज के विस्तार के संबंध में 25 केवी ओएचई रूपांतरण। **कार्य की अनुमानित लागत :** रु. 29,47,596/-, **निविदा प्रपत्र की लागत :** शून्य। **बयाना राशि/बोली सुरक्षा जमा की जानी है:** रु. 59,000/-, **कार्य समाप्ति की अवधि :** एलओए जारी करने की तिथि से 12 (बारह) माह। **निविदा समापन तिथि और समय:** दिनांक 10.06.2026 को 15.00 बजे। **निविदा का खुलना:** निविदा के बंद होने के बाद किसी भी समय निविदा खोली जाएगी। निविदाकार निविदा के संपूर्ण विवरण/वर्णन/विनिर्देश के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देख सकते हैं एवं अपनी बोली ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं कोई मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

HWH-75/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक बढ़ी

कोलकाता, समाज्ञा

राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ए, बी, सी, और डी समूह की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए संशोधित आयु सीमा वित्त विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद 11 मई से प्रभावी हो गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (डब्ल्यूबीपीएससी) के जरिए भर्ती के लिए संशोधित नियमों के तहत ग्रुप 'ए' पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 41 वर्ष, ग्रुप 'बी' पदों के लिए 44 वर्ष और ग्रुप 'सी' तथा ग्रुप 'डी' पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन पदों के लिए पहले से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा इससे अधिक है, वहां मौजूदा सीमा ही लागू रहेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों जैसे वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया कॉलेज सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए होगी, जिसकी चयन प्रक्रिया जारी है। विज्ञप्ति में कहा गया कि चूंकि, कॉलेज सेवा आयोग एक राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है, इसलिए इस भर्ती में पहले की 40 वर्ष की सीमा के बजाय संशोधित 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू होगी। सरकार ने यह भी कहा कि सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाई जाएगी ताकि नए पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। सरकार ने कहा कि हमें विश्वास है कि इस फैसले से राज्य में खासकर उन अभ्यर्थियों की सरकारी रोजगार के अवसरों तक पहुंच काफी बढ़ेगी जो पहले की आयु सीमा को मामूली अंतर से पार कर चुके थे। अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलने वाली मौजूदा आयु छूट पहले की तरह जारी रहेगी।

2021 के चुनाव बाद हिंसा से जुड़े 59 मामलों को फिर खोला गया, 181 नयी प्राथमिकी दर्ज

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल सीआईडीने 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के संबंध में नए सिरे से कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत 458 नयी जांच शुरू करते हुए 181 नयी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उन 59 मामलों को भी फिर से खोला है जिनमें पहले अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी। एक वरिष्ठ सीआईडी अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित शिकायतों को देखते हुए, प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीआईडी अधिकारी ने कहा कि एजेंसी उन मामलों की भी दोबारा जांच कर रही है जिन्हें पहले बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब तक जिन 59 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की जा चुकी थी, उन्हें भी जांच के लिए फिर से खोला गया है। यह प्रक्रिया जारी है।

फिर खुलेगी 'मेस्सी कांड' की फाइल, दर्शकों को लौटाए जाएंगे टिकट के पैसे : मंत्री निशिथ प्रमाणिक

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में नवगठित भाजपा सरकार पिछले साल दिसंबर में कोलकाता के युवाभारती क्रीड़ांगन में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेस्सी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले की फाइल फिर से खोलने जा रही है। राज्य के खेल मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने बताया कि इस मामले से जुड़ी सभी फाइलें औपचारिक रूप से मंगाई गई हैं और पूरे घटनाक्रम की नई सिरे से जांच कराई जाएगी। प्रमाणिक ने कहा कि सरकार शुरू से ही उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें 'मेस्सी कांड' में अपमान और धोखे का सामना करना पड़ा। मामले में जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन फुटबाल प्रेमियों ने महंगे टिकट खरीदे थे, उन्हें उनकी मेहनत की कमाई लौटाई जाएगी। सरकार ने कार्यक्रम आयोजकों को साफ निर्देश दिया है कि दर्शकों को टिकट का पैसा वापस किया जाए। जरूरत पड़ने पर खेल विभाग इस प्रक्रिया में मदद करेगा।

❑ साल्टलेक स्टेडियम के बाहर से ममता की डिजाइन की गई प्रतिमा हटायेगी सरकार

राज्य सरकार साल्टलेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली उस विवादित मूर्ति को हटायेगी जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था। राज्य के खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति देखने में बेहद भद्दी है। धड़ के पास से कटे हुए दो पैर और उनके ऊपर एक फुटबॉल, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यह देखने में भी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती, इसलिए हम इस तरह की बेतुकी और अर्थहीन बनावट को यहां नहीं रखेंगे, और इसे हटा दिया जाएगा। प्रमाणिक ने कहा कि जब से यह मूर्ति लगी है, पिछली सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए। इसके बाद, मेस्सी विवाद हुआ और सरकार की सत्ता भी चली गई। उन्होंने विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के आसपास फूड कोर्ट बनाने से लेकर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का भी ऐलान किया।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं. : 222-एस/1/डब्ल्यू-II, दिनांक 15.05.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए निम्नलिखित ई-निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है: **क्रम सं. : 1, निविदा सं.: टीएन-35-26-27, कार्य का नाम:** मंडल अभियंता/III/सियालदह के कार्यक्षेत्र में सहायक अभियंता/बहरमपुर कोर्ट के अधीन बहरमपुर कोर्ट स्टेशन में प्लेटफॉर्म नं. 1 एवं आइलैंड प्लेटफॉर्म नं. 2/3 के प्लेटफॉर्म का विस्तार। **निविदा मूल्य :** रु. 5,38,54,010.96, **बयाना राशि :** रु.10,77,100/-, **कार्य की समापन अवधि:** 08 (आठ) माह। **क्रम सं. : 2, निविदा सं.: टीएन-36-26-27, कार्य का नाम:** वरिष्ठ मंडल अभियंता/1/सियालदह के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदारों के मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट के साथ साइट पर 60 केजी/52 केजी (90 यूटीएस/72 यूटीएस, आर-260) (नई/एसएच/एसआर/एसडब्ल्यूआर/एलडब्ल्यूआर) रेल की फ्लैश बट वेल्डिंग। **निविदा मूल्य :** रु. 4,17,31,580.06, **बयाना राशि :** रु.8,34,600/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 (बारह) माह। **क्रम सं. : 3, निविदा सं.: टीएन-37-26-27, कार्य का नाम:** वरिष्ठ मंडल अभियंता/II/सियालदह के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदारों के मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट के साथ साइट पर 60 केजी/52 केजी (90 यूटीएस/72 यूटीएस, आर-260) (नई/एसएच/एसआर/एसडब्ल्यूआर/एलडब्ल्यूआर) रेल की फ्लैश बट वेल्डिंग। **निविदा मूल्य :** रु. 5,52,38,890.29, **बयाना राशि :** रु.11,04,800/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 (बारह) माह। **क्रम सं. : 4, निविदा सं.: टीएन-38-26-27, कार्य का नाम:** मंडल अभियंता/3/सियालदह के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदारों के मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट के साथ साइट पर 60 केजी/52 केजी (90 यूटीएस/72 यूटीएस, आर-260) (नई/एसएच/एसआर/एसडब्ल्यूआर/एलडब्ल्यूआर) रेल की फ्लैश बट वेल्डिंग। **निविदा मूल्य :** रु. 2,73,58,501.50, **बयाना राशि :** रु.5,47,200/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 (बारह) माह। **क्रम सं. : 5, निविदा सं.: टीएन-39-26-27, कार्य का नाम:** मंडल अभियंता (मुख्यालय)/सियालदह के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदारों के मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट के साथ साइट पर 60 केजी/52 केजी (90 यूटीएस/72 यूटीएस, आर-260) (नई/एसएच/एसआर/एसडब्ल्यूआर/एलडब्ल्यूआर) रेल की फ्लैश बट वेल्डिंग। **निविदा मूल्य :** रु. 2,73,58,501.50, **बयाना राशि :** रु.5,47,200/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 (बारह) माह। **क्रम सं. : 6, निविदा सं.: टीएन-40-26-27, कार्य का नाम:** सियालदह मंडल में विभिन्न रेलवे यार्ड के टोपोग्राफिकल सर्वे, सीमित ऊंचाई के सबवे (एलएचएस) के जीएडी और उससे जुड़ी जियोटेक्निकल जांच का प्रावधान। **निविदा मूल्य :** रु. 2,08,43,097.27, **बयाना राशि :** रु.4,16,900/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 (बारह) माह। **निविदा की अंतिम तिथि और समय:** दिनांक 10.06.2026 को 15.00 बजे (क्रम सं. 1 से 6 हेतु)। **निविदा के खुलने की तिथि और समय:** दिनांक 10.06.2026 को 15.00 बजे (क्रम सं. 1 से 6 हेतु)। निविदा कागजात एवं विवरण वेबसाइट: **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा के लिए बोली उपर्युक्त वेबसाइट पर ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी। मैनुअल प्रस्ताव को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे मानक अनुबंध 2022 की सामान्य शर्तों के अनुसार, ई-निविदा प्रपत्र की लागत शून्य है।

SDAH-45/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना संख्या : ईएल/एचडब्ल्यूएच/25/21 (सूचना)/757, दिनांक 15.05.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा, नई डीआरएम बिल्डिंग, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा निम्नलिखित विद्युत कार्य के लिए ओपन ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं : **क्रम सं. 1, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3617, कार्य का नाम :** टिकियापाड़ा और सॉर्टिंग यार्ड डिपो से शुरू होने वाले विभिन्न रेक के कमिंस इंडिया लिमिटेड प्रस्तुतकारक के डीजी सेट से सज्जित पावर कारों की 2 वर्ष के लिए एस्कॉर्टिंग, संचालन और ए-चेक मेंटेनेंस। **निविदा मूल्य :** रु. 13,28,53,031/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 8,14,300/-, **पूर्णता अवधि:** 24 माह। **क्रम सं. 2, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3618, कार्य का नाम :** टिकियापाड़ा और सॉर्टिंग यार्ड डिपो से शुरू होने वाले विभिन्न रेक के किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड (केओईएल) प्रस्तुतकारक के डीजी सेट से सज्जित पावर कारों की 2 वर्ष के लिए एस्कॉर्टिंग, संचालन और ए-चेक मेंटेनेंस। **निविदा मूल्य :** रु. 5,53,36,075/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 4,26,700/-, **पूर्णता अवधि:** 24 माह। **समापन तिथि एवं समय:** दिनांक 29.05.2026 को 15.00 बजे क्रम सं. 1 एवं 2 के लिए। यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समापन तिथि को अवकाश/ बंद/हड़ताल घोषित किया जाता है, तो ऑनलाइन निविदा जमा करने की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईआरईपीएस वेबसाइट पर समापन तिथि और समय के बाद कोई निविदा जमा नहीं की जा सकती। हालांकि, निविदाओं का ऑनलाइन उद्घाटन समापन तिथि के बाद किसी भी सुविधाजनक दिन किया जा सकता है। निविदा का पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदाकारों से अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट पर अपनी निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

HWH-67/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सं. : 40_2026-27, दिनांक: 12.05.2026, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (IV), पूर्व रेलवे, हावड़ा, नई डीआरएम बिल्डिंग, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा -711101 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए सिंचाई/सीपीडब्ल्यूडी/एसईबी/ एमईएस या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पंजीकृत समेत समप्रकृति के कार्य के अनुभवी एवं अपेक्षित वित्तीय संपन्न निविदाकारों से निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **वरिष्ठ डीईएन/4/हावड़ा। कार्य का विवरण :** हावड़ा मंडल के तहत बैण्डेल, बर्द्धमान, आजिमगंज और रामपुरहाट में रेलवे इंस्टीट्यूट का नवीनीकरण। **अनुमानित मूल्य :** रु. 3,01,17,121.64, **बयाना राशि :** रु. 6,02,400/-, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.) :** शून्य। **समापन अवधि :** स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से 12 (बारह) माह। यदि निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित अंतिम तिथि को किसी भी कारण से अवकाश/बंद/हड़ताल घोषित किया जाता है, तो ऑनलाइन निविदा की अंतिम तिथि नहीं बदली जाएगी क्योंकि आईआरईपीएस की वेबसाइट में किया गया आवेदन, निविदा की अंतिम तिथि और समय के बाद किसी भी प्रस्ताव को जमा करने की अनुमति नहीं देता है। तथापि निविदाओं का ऑनलाइन खोला जाना अगले कार्यदिवस में किया जाएगा। **निविदा की अंतिम तिथि और समय :** दिनांक 04.06.2026 को 14.00 बजे। निविदा का विवरण वेबसाइट : **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदाकारों से अनुरोध किया जाता है कि अपने प्रस्ताव को उपर्युक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करें। ई-निविदा प्रणाली के मामले में, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और निविदा कागजात की लागत (टीडीसी) का भुगतान, केवल नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से उपर्युक्त वेबसाइट के जरिए स्वीकार किया जाएगा। **टिप्पणी:** आईआरईपीएस (ई-निविदा पोर्टल) पर आमंत्रित निविदाओं के लिए ईएमडी के रूप में कोई फिक्सड डिपॉजिट रिसीट (एफडीआर) स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

HWH-69/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का किया अनुरोध

कोलकाता, समाज्ञा : तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मामले की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। बता दें कि पुलिस ने विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पांच मई को बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बागुईआटी थाने में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दायर शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट से जहांगीर खान को राहत, 26 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के सिलसिले में पुलिस की ओर से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से 26 मई तक सुरक्षा प्रदान कर दी। बता दें कि खान के वकील किशोर दत्ता ने इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत का रुख किया। उन्होंने अदालत से अपने मुवक्किल के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों का विवरण देने और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। अदालत ने निर्देश दिया कि लंबित आपराधिक मुकदमों के संबंध में खान के खिलाफ 26 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने खान को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता आदेश का उल्लंघन करता है, तो पुलिस अधिकारी इसे अदालत के संज्ञान में ला सकते हैं। अदालत ने तृणमूल उम्मीदवार से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने और मतदाताओं एवं अन्य हितधारकों को डराने-धमकाने से बचने को कहा। उसने खान को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए पुनर्मतदान के लिए प्रचार करने की अनुमति भी दे दी।

पूर्व महाधिवक्ता दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि खान फलता विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, जहां 21 मई को पुनर्मतदान होना है। दत्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि चुनाव परिणाम के बाद राज्य में राजनीतिक परिदृश्य बदलने के कारण खान के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में मुकदमा शुरू किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि पांच से 15 मई के बीच फलता थाने में खान के खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज किए गए। खान की याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने अदालत के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता के आचरण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को डराने-धमकाने, बूथ कब्जाने और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ सहित बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों के बाद दो मई को फलता निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता 29 अप्रैल को फलता में चुनाव के दिन कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई धांधली का साजिशकर्ता था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि याचिकाकर्ता को लोकतांत्रिक अधिकारों की भावना को जीवित रखने के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि लेकिन इसके साथ ही, अदालत को चुनाव लड़ने के याचिकाकर्ता के अधिकार और उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के संबंध में जांच जारी रखने के बीच संतुलन बनाने रखने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों का नियंत्रण

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के कटिहार-सोनाली और कटिहार-कुरेठा खंडों में दोहरी लाइन की शुरुआत के लिए, कटिहार, मनियां, कुरेठा, डंडखोरा और सोनाली स्टेशनों पर तीन दिनों के लिए बिफोर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य, तीन दिनों के लिए प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य, तीन दिनों के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के साथ ही साथ एक दिन के लिए सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, ट्रेनों के परिचालन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं: • **ट्रेनों की रद्दगी: 55702/55701** कटिहार-मालदा टाउन-कटिहार पैसेंजर (दोनों की यात्रा शुरू की तारीख 10.06.2026, 11.06.2026, 12.06.2026, 13.06.2026, 14.06.2026)। • **संक्षिप्त यात्रा समाप्त/संक्षिप्त यात्रा शुरू:** 13159 कोलकाता-जोगबनी एक्सप्रेस (यात्रा शुरू की तारीख 10.06.2026 और 12.06.2026) और **13160** जोगबनी-कोलकाता एक्सप्रेस (यात्रा शुरू की तारीख 11.06.2026 और 13.06.2026) को **कटिहार** में/से संक्षिप्त यात्रा समाप्त/संक्षिप्त यात्रा शुरू करेंगी और दोनों दिशाओं में कटिहार तथा जोगबनी स्टेशनों के बीच इनकी सेवायें रद्द रहेंगी। • **ट्रेन का मार्ग परिवर्तन: 15925** देवघर-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (यात्रा शुरू की तारीख 11.06.2026) कटिहार-पूर्णिया-अररिया-पाबाखाली-ठाकुरगंज होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन बरसोई और किशनगंज स्टेशनों पर नहीं रुकेगी तथा पूर्णिया और ठाकुरगंज स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करेगी। • **ट्रेन का नियंत्रण: 15625** देवघर-अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस (यात्रा शुरू की तारीख 08.06.2026) इसे मार्ग में **90 मिनट** के लिए नियंत्रित किया जाएगा (यदि सही समय पर चलती है)। असुविधा के लिए खेद है।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

गांवों में नल से जल की अपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए बंगाल ने केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य सरकार ने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि 'जल जीवन मिशन' के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति करने के दायरे को बढ़ाने में तेजी लाई जा सके। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान इस योजना में देरी, धनराशि के कम उपयोग और क्रियान्वयन में खामियां रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 'डबल इंजन सरकार' राज्य में स्पष्ट बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। यह एमओयू एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें पाटिल, जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और वरिष्ठ अधिकारी डिजिटल तरीके से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि बंगाल के लोग लंबे समय से इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे थे और पूर्ववर्ती वर्षों में जमीनी स्तर पर इसकी सीमित प्रगति हुई। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहते हुए उन्होंने कई गांवों का दौरा किया था और पाया कि योजना का अधिकतर काम सिर्फ कागजों पर ही था। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत 39,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका लक्ष्य घर-घर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से अधिक सहायता की भी मांग की और कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति के कारण बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा कार्य बिना केंद्र की मदद के संभव नहीं है।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री पाटिल ने पश्चिम बंगाल में इसके क्रियान्वयन की गति पर चिंता जताते हुए कहा कि ग्रामीण घरों में नल जल कवरेज 2019 में एक प्रतिशत से बढ़कर अब 56 प्रतिशत हो गया है, लेकिन स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में जल आपूर्ति के मामले में राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत 33,363 करोड़ रुपये मिले हैं, जिनमें से 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 11,670 करोड़ रुपये अब भी उपयोग नहीं हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से गंगा किनारे मलजल शोधन संयंत्र के लिए भूमि आवंटन तेज करने और मानसून से पहले वर्षा जल संचयन को बढ़ाने की भी अपील की। पाटिल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस एमओयू को मंजूरी दी है, जिससे इसका क्रियान्वयन अनिवार्य हो गया है।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव॥

www.samagya.in

समाज्ञा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

• MATRIMONIAL • EDUCATION • OBITUARY
• PROPERTY • NAME CHANGE • REMEMBRANCE
• RECRUITMENT • PUBLIC NOTICE • DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadvt@gmail.com | www samagya.in

230, C. R. Ave, 3rd Floor, Kolkata-700 006, Contact : 7044444522, 7044444527

स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश, मेरिट के आधार पर ही होगी नियुक्ति

कोलकाता : राज्य के स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने को लेकर सोमवार को सॉल्टलेक स्थित स्वास्थ्य भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने राज्य के नौ चिकित्सक-विधायकों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा जंगलमहल क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी नियुक्तियां केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर होंगी। काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की सिफारिश, पक्षपात या स्वजनपोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में कथित कटमनी संस्कृति और सिंडिकेट राज के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया गया। सूत्रों के अनुसार, मेडिकल काउंसिल, हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के अन्य हिस्सों में पूर्व में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

जंगलमहल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करने की योजना पर चर्चा हुई, ताकि गंभीर दुर्घटनाओं या न्यूरोलॉजिकल चोटों के मरीजों को इलाज के लिए कोलकाता या दूसरे राज्यों में रेफर न करना पड़े। इसके अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चठख और उढ स्कैन मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

आरजी कर मामले के बाद स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को मुख्यमंत्री का अचानक तलब

कोलकाता : स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अचानक नवान्न तलब किया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही कई निर्देश दे चुके हैं। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य भवन में एक अहम बैठक चल रही थी, तभी नारायण स्वरूप निगम को तत्काल नवान्न बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बीच में ही उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना होना पड़ा। इस अचानक तलब को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विशेषकर आरजी कर प्रकरण के बाद स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कई आरोप सामने आए थे। आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें पद से हटाने की मांग भी उठाई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग में बड़े प्रशासनिक फैसले ले सकते हैं।

राज्य में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हर ब्लॉक में खुलेगा 'पीएम श्री' स्कूल : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने व आधुनिक बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा करते हुए सरकारी व निजी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों को कड़ा संदेश दिया। कोलकाता के धनधान्य ऑडिटोरियम में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई के मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था राजनीति के चंगुल से मुक्त होगी। हर ब्लॉक में कम से कम एक 'पीएम श्री'स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने निजी शिक्षण संस्थानों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अनैतिक रूप से फीस बढ़ाना या पैसों के बदले सर्टिफिकेट बांटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब स्कूल-कालेजों की गवर्निंग बॉडी (संचालन समिति) में कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि या विधायक शामिल नहीं होगा।

❑ **शुरू हुई विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप**

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मेधा व आर्थिक जरुरतों के आधार पर छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने छात्र समुदाय को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ है।

32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्दीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब

नई दिल्ली/कोलकाता : प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के मामले में देश की शीर्ष अदालत के जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने सोमवार को नोटिस जारी कर सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में की जा सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जोरदार पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की इस नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर 'संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने दलील दी कि नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर अयोग्य लोगों को नौकरियां बांटी गईं, इसलिए अदालत को इस पूरी भर्ती के पैनल को ही रद्द कर देना चाहिए।

आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में ईडी को संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज मुख्यमंत्री के रूप में एक महान और सकारात्मक कदम उठाने पर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिस्टर अभया की क्रूर हत्या और दुष्कर्म के मामले में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी को कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरदस्ती और अनैतिक रूप से रोके रखा। लेकिन हमारा माननाहै कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि सिस्टर अभया के असली दोषियों की जल्द से जल्द पहचान हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और राज्य की जनता को न्याय मिले। मैं सिस्टर अभया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार पर जोर, मंत्रियों के लिए साफ छवि वाले अधिकारियों की तैनाती

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भाजपा सरकार ने सोमवार को नई कैबिनेट के मंत्रियों के लिए कई पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) अधिकारियों को 'एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट' नियुक्त किया। सूत्रों के मुताबिक, इन अधिकारियों का चयन उनकी साफ-सुथरी, पारदर्शी और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियुक्तियों को लेकर अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया है। 2013 बैच के डब्ल्यूबीसीएस अधिकारी बिस्वनाथ चौधरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नियुक्त किया गया है। चौधरी फिलहाल हुगली जिला परिषद में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं, 2016 बैच के अधिकारी कृष्ण चंद्र मुंडा को पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री खुदीराम टुडु का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनाया गया है। वह वर्तमान में बांकुड़ा जिले में डिप्टी मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात हैं। इसके अलावा, 2016 बैच के ही अधिकारी कौशिक कुमार मैती को खाद्य एवं आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्री अशोक कीर्तनिया का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नियुक्त किया गया है। मैती अभी दक्षिण 24 परगना के जिला योजना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। नवान्न के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन अधिकारियों का चयन उनके सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद किया गया है। चयन प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासनिक छवि को प्राथमिकता दी गई।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग की अपील

कोलकाता : राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य से सोमवार को विकास भवन में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रासबिहारी के विधायक एवं शिक्षाविद् स्वपन दासगुप्ता तथा सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष मौजूद रहे। बैठक में राज्य की शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण, नीतिगत बदलाव और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद विधायक शंकर घोष ने कहा कि नई सरकार शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। शिक्षक और छात्रों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उसे पूरी गंभीरता के साथ निभाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति से आगे बढ़कर शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए सरकार सभी संबंधित पक्षों का सहयोग चाहती है। सरकार शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की राय लेकर भविष्य की शिक्षा नीति तय करेगी। शंकर घोष ने कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण और बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में पूर्व चेयरमैन पाचू राय से ईडी ने की पूछताछ

कोलकाता, समाज्ञा : नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिण दमदम नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन पाचू राय को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें सॉल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय बुलाया गया, जहां वह सुबह ही पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार, नगरपालिका में अवैध नियुक्तियों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में इसी मामले में गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस के साथ पाचू राय का आमना-सामना कराकर भी पूछताछ की जा सकती है। सुजीत बोस फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उल्लेखनीय है कि नगर निगम भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल आरोपपत्र में भी पाचू राय का नाम शामिल है। इससे पहले भी इस मामले की जांच के सिलसिले में ईडी उन्हें कई बार तलब कर चुकी है और वह पूछताछ में शामिल होते रहे हैं। हालांकि, पाचू राय ने पहले सभी आरोपों से इनकार किया था। उनका दावा था कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और उन्हें केवल परेशान करने के उद्देश्य से पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

नौ घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने कुख्यात 'सोना पप्पू' को किया गिरफ्तार

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता के कस्बा इलाके के कुख्यात अपराधी विश्वजीत पोद्दार उर्फ 'सोना पप्पू' को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। वित्तीय धोखाधड़ी और कथित वसूली मामले में लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार, इस दिन, सुबह में सोना पप्पू अपनी पत्नी को साथ लेकर साल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वहां करीब नौ घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान उसने सहयोग नहीं किया। अधिकारी के मुताबिक, पोद्दार को मंगलवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष फरवरी में रवींद्र सरोवर थाना क्षेत्र में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटना में भी विश्वजीत पोद्दार का नाम सामने आया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि घटना के पीछे उन्हीं का हाथ था और उनके सहयोगियों ने इलाके में उपद्रव मचाया था। हालांकि, उस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन पुलिस लंबे समय तक सोना पाप्पू तक नहीं पहुंच सकी थी। इस दौरान, उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर दावा किया था कि उनका किसी भी हिंसक घटना से कोई संबंध नहीं है। मामले की जांच के दौरान ईडी ने अचानक उनके आवास पर छापेमारी की थी।

रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर पटरी पर कूदा यात्री

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता की मेट्रो रेल में सोमवार को एक बार फिर बड़ी अप्रिय घटना सामने आई है। शाम के व्यस्त समय में एक यात्री द्वारा मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या की कोशिश किए जाने से हड़कंप मच गया। घटना शाम करीब 4.10 बजे रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर हुई। इस हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से तुरंत बिजली आपूर्ति (पावर सप्लाई) काट दी गई और ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। व्यस्त समय में मेट्रो सेवा बाधित होने के कारण हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और मेट्रो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस दिन, शाम को अन्य दिनों की तरह रवींद्र सरोवर स्टेशन पर यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ थी। शाम 4:10 बजे जैसे ही एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई, तभी एक यात्री ने अचानक पटरी (डाउन लाइन) पर छलांग लगा दी। चालक ने तत्परता दिखाते हुए ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक यात्री ट्रेन के नीचे आ चुका था। स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित कर पटरियों की बिजली आपूर्ति बंद कराई और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य (रेस्क्यू ऑपरेशन) शुरू किया गया। इस दुर्घटना के कारण कवि सुभाष से दक्षिणेश्वर जाने वाली मुख्य लाइन पर मेट्रो का परिचालन काफी देर तक पूरी तरह बंद रहा। बाद में, स्थिति को संभालने के लिए मेट्रो अधिकारियों ने आंशिक रूप से (कंट्रोल सर्विस) ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। हालांकि, बीच के स्टेशनों पर सेवा बंद होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई।

भीषण गर्मी में एनडीआरएफ ने राहगीरों में किया सरबत वितरण

कोलकाता : बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एनडीआरएफ की 2वीं वाहिनी अंतर्गत रिजनल रिस्पांश सेंटर (आरआरसी), कोलकाता द्वारा रविवार को राहगीरों और स्थानीय लोगों में सरबत वितरण किया गया। सरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन 2वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट मनीष रंजन के मार्गदर्शन तथा सहायक कमांडेंट संतोष कुमार ठाकुर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान एनडीआरएफ टीम ने बड़ी संख्या में राहगीरों और स्थानीय लोगों के बीच सरबत वितरित कर गर्मी से राहत पहुंचाई। इस पहल का उद्देश्य लोगों को भीषण गर्मी में शरीर में पानी की कमी से बचने, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने और हाइड्रेटेड रहने के प्रति जागरूक करना था। एनडीआरएफ अधिकारियों ने कहा कि बल केवल आपदा राहत और बचाव कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनकल्याण और सामुदायिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। गर्मी के इस मौसम में आयोजित यह मानवीय पहल लोगों के बीच काफी सराही गई।

विक्रसम विहार में 9 दिवसीय श्री राम कथा

कोलकाता : पावन पुरुषोत्तम मास में विक्रम विहार में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, व्यास पीठ पर विराजमान है अमरावती दीदी जो अयोध्या से पधारी है। आज कथा में उन्होंने बहुत सार गर्भित श्री राम चरित मानस से बातें बताई, उन्होंने कहा रामायण हर समस्या का समाधान है और उसके एक एक चरित्र अनूठे है, हमको बाल्यकाल से ही श्री राम जी कि कहानियां सुनने को मिलती हैं और हमें उसका अनुसरण करना चाहिये। कथा श्रवण करने पूरा विक्रम विहार का हॉल भर गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में कविता मित्तल, मंजू अग्रवाल और पन्नालाल अग्रवाल कि प्रमुख भूमिका रही।

योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गोपाल मंदिर में बही साहित्य की बयार

कोलकाता, समाज्ञा : दमदम सेंट्रल जेल के समीप स्थित ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में बीते दिन अध्यात्म और साहित्य का एक अनूठा संगम देखने को मिला जहां आयोजित भव्य काव्य गोष्ठी में शब्दों और संवेदनाओं की अनूठी बयार बही। कार्यक्रम का शुभारंभ कवयित्री प्रणति ठाकुर द्वारा प्रस्तुत मधुर सरस्वती वंदना से हुआ। इस साहित्यिक महाकुंभ का अत्यंत कुशल और जीवंत संचालन प्रख्यात रचनाकार आदित्य त्रिपाठी ने किया। इस गरिमामयी शाम में बतौर मुख्य अतिथि 'रॉयल सिक्योरिटी लिमिटेड' के प्रबंध निदेशक तारक नाथ दुबे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में 'कोल इंडिया' के मुख्य सतर्कता अधिकारी बृजेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष सुजीत चक्रवर्ती, सचिव अजय सिंह और कोषाध्यक्ष दिलीप ठाकुर के नेतृत्व में कैलाशपति सिंह जोधन, बी एन मिश्रा, डी डी मिश्र, हरिचरण सिंह, हरिहर रॉय, मनोज चौबे, भुवनेश्वर सिंह, आर एन धारा, आर एन दुबे, एस एन मिश्रा, काशीनाथ तिवारी, निरंकार मिश्रा, संगीता शुक्ला, सीमा राय, विमला सिंह और सुधा अग्रवाल ने सभी आमंत्रित कवियों और कवयित्रियों को पुष्प गुच्छ व सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया। अंत में, समिति द्वारा सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ इस सफल और यादगार काव्योत्सव का समापन हुआ।

निमता से 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, आश्रय देने वाले एक व्यक्ति को भी दबोचा गया

❑ **आरोपियों के पास से फर्जी आधार, पैन, ई-राशन कार्ड बरामद, पैसे देकर भारत में ली थी एंट्री**

कोलकाता, समाज्ञा : उत्तर 24 परगना जिले के निमता थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन्हें अवैध रूप से अपने घर में पनाह देने और दस्तावेज बनवाने में मदद करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को भी दबोचा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास से भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) भी बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को निमता के गोलबागान इलाके में पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ दिखाई दिया। निमता थाने की पुलिस ने जब उसे रोककर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रविवार की रात निमता के फतुल्लापुर इलाके में छापेमारी की। वहां से मकान मालिक और मुख्य मददगार शाहिदुल इस्लाम (भारतीय नागरिक) समेत कुल 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी आरोपियों को सोमवार को बैरकपुर अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्राथमिक पूछताछ में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सीमा पार करने के लिए एजेंटों को मोटी रकम दी थी और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। भारत आने के बाद वे निमता के फतुल्लापुर में रहने वाले शाहिदुल इस्लाम के घर पर किराए पर रहने लगे। शाहिदुल मोटी रकम के बदले इन अवैध घुसपैठियों को अपने घर में रखता था। जांच में यह भी सामने आया है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद इन नागरिकों ने स्थानीय सिंडिकेट की मदद से भारतीय पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए थे। इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्होंने भारतीय बैंकों में अपने खाते भी खुलवा लिए थे और यहीं रहकर काम-काज करने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन विदेशी नागरिकों के भारतीय दस्तावेज बनाने के पीछे और कौन-कौन से लोग शामिल हैं।

बांसबेड़िया से तृणमूल नेता वैद्यनाथ साहा गिरफ्तार

हुगली : मगरा थाना पुलिस ने बांसबेड़िया के प्रमुख समाजसेवी और तृणमूल नेता वैद्यनाथ साहा को गिरफ्तार किया है। उन्हें कल्याणी ईश्वर गुप्त सेतु के टोल प्लाजा इलाके से हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बांसबेड़िया निवासी लक्ष्मण चौधरी 21 अगस्त 2025 से लापता हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इस मामले में परिजनों ने मगरा थाने में कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहले ही इलाके के तीन युवकों शिवनाथ साहू, अम्लान और विजय को गिरफ्तार किया था। कई महीनों बाद सत्ता परिवर्तन के पश्चात पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज करते हुए वैद्यनाथ साहा को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि वैद्यनाथ साहा कल्याणी से दो चार पहिया वाहनों में बांसबेड़िया की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने ईश्वर गुप्त सेतु के टोल प्लाजा के पास घेराबंदी की और वाहन पहुंचते ही उन्हें रोककर वैद्यनाथ साहा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें मगरा थाने ले गई। वहां से मेडिकल जांच के लिए पहले मगरा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें चूंचूड़ा अदालत में पेश किया गया।

'द कॉल ऑफ द ब्लू' वीकेंड इवेंट से कोलकाता में छाया यामाहा का रोमांच

कोलकाता, समाज्ञा : यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप ने अपने ब्रांड कैंपेन 'द कॉल ऑफ द ब्लू' के तहत न्यूटाउन स्थित ईको पार्क गेट नंबर 4 में भव्य वीकेंड इवेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम में 3000 से अधिक राइडर्स, बाइक प्रेमी और यामाहा फैंस शामिल हुए। इवेंट में यामाहा के प्रीमियम टू-व्हीलर्स का प्रदर्शन किया गया, जहां प्रतिभागियों को कंपनी के रेसिंग डीएनए और हाई-परफॉर्मेंस बाइकिंग कल्चर का अनुभव मिला। कार्यक्रम में जिमखाना राइड, स्लो बैलेंसिंग चैलेंज, गेमिंग एरीना और सेफ्टी राइडिंग क्लासेस जैसी कई आकर्षक गतिविधियां आयोजित की गईं। यह आयोजन यामाहा और नॉन-यामाहा दोनों यूजर्स के लिए खुला था, जिससे जिम्मेदार राइडिंग को बढ़ावा देने के साथ बाइकिंग समुदाय को एक मंच मिला। कार्यक्रम में अंडरग्राउंड अथॉरिटी बैंड की लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस ने माहौल को और ऊर्जावान बना दिया। यामाहा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत में राइडिंग कल्चर को मजबूत करना और युवाओं को कंपनी के प्रीमियम व हाई-परफॉर्मेंस प्रोडक्ट लाइनअप से जोड़ना है।

पूर्व रेलवे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, मथुरापुर स्टेशन पर आधुनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली शुरू

❑ **सुरक्षा और ट्रैक अपग्रेड पर विशेष जोर**

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे ने आसनसोल मंडल में 7 घंटे का मेगा पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेकर बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना उन्नयन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभियान पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर के नेतृत्व तथा आसनसोल मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य की निगरानी में संचालित किया गया। इस दौरान मथुरापुर स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली शुरू की गई, जिससे अब 49 अलग-अलग ट्रेन रूटों का संचालन संभव होगा। यार्ड रीमॉडलिंग के तहत गुड्स व्हार्फ लाइन और अप साइडिंग की लंबाई 554 मीटर से बढ़ाकर 795 मीटर की गई, जबकि अप लूप लाइन को भी विस्तारित किया गया। इसके अलावा, नई कॉमन लूप लाइन बनाई गई तथा डाउन मेन लाइन को कॉमन लाइन में परिवर्तित किया गया।

रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुराने ब्लॉक सिस्टम की जगह डिजिटल फेल-सेफ इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की। लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 23 को इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर में बदला गया तथा अन्य लेवल क्रॉसिंग पर भी सुरक्षा सुधार किए गए। मेगा ब्लॉक के दौरान आसनसोल, सीतारामपुर, साल-ानपुर और सीतारामपुर लिंक केबिन सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर 17 वेल्डेबल कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग लगाए गए। इसके साथ ही ट्रैक नवीनीकरण, रेल वेल्डिंग, ट्रैक टैम्पिंग और ओवरहेड इक्विपमेंट अपग्रेड का कार्य भी पूरा किया गया। रेलवे ने 72 अल्युमिनो थर्मिट वेल्डिंग, 20 किलोमीटर ट्रैक टैम्पिंग और कई स्थानों पर रेल नवीनीकरण का काम किया।

वहीं, विद्यासागर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का स्ट्रक्चरल अपग्रेड किया गया, जबकि जामताड़ा, मधुपुर और सीतारामपुर स्टेशनों पर पुराने गर्डरों को हटाया गया। ट्रैक्शन विभाग ने ओवरहेड वायर, आ-इसोलेटर और कैटेनेरी उपकरणों का भी आधुनिकीकरण किया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन कार्यों से ट्रेनों की गति, समयपालन और यात्री सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। मथुरापुर स्टेशन पर ट्रैक टर्नआउट और क्रॉसओवर अपग्रेड होने से ट्रेनों की गति 15 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सिग्नलिंग में मानवीय त्रुटि की संभावना भी काफी कम होगी।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने कहा कि 7 घंटे के मेगा ब्लॉक के दौरान कई दिनों के जटिल इंजीनियरिंग कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सभी अपग्रेड यात्रियों को सुरक्षित, समयनिष्ठ और अधिक आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए गए हैं।

हावड़ा ब्रिज पर अनियंत्रित सरकारी बस पिलर से टकराई, 13 यात्री घायल

हावड़ा, समाज्ञा : हावड़ा ब्रिज पर सोमवार को एक सरकारी बस अचानक अनियंत्रित होकर पुल के पिलर से जा टकराई। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अंदर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में जा रही थी। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे पिलर से भिड़ गई। दुर्घटना में कुल 13 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्प-ताल भेजा गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए इलाके पर यातायात प्रभावित रहा। फिलहाल, स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे के कारणों की जांच कर रही हैं।

3 मंजिल की अनुमति लेकर बना दी 6 मंजिली इमारत

❑ हावड़ा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

हावड़ा, समाज्ञा : राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब हावड़ा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार दोपहर हावड़ा नगर निगम ने चटर्जीहाट इलाके के शरत चटर्जी रोड स्थित एक निर्माणाधीन इमारत को तोड़ने का अभियान शुरू किया। आरोप है कि तीन मंजिला भवन निर्माण की अनुमति लेकर वहां छह मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। सोमवार दोपहर नगर निगम के अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों और बुलडोजर के साथ शरत चटर्जी रोड पहुंचे। इसके बाद 27 नंबर शरत चटर्जी रोड स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया गया।

जानकारी के अनुसार, जमीन के मालिक का नाम विष्णुपद दत्त है। उनकी पुरानी इमारत को तोड़कर वहां प्रमोटर पंकज दत्त फ्लैट निर्माण का काम कर रहे थे। करीब 9 महीने पहले इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, उस जमीन पर केवल तीन मंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां छह मंजिला भवन निर्माण किए जाने का आरोप सामने आया।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार ने हावड़ा नगर निगम को अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी निर्देश के तहत नगर निगम ने तत्काल ध्वस्त किए जाने वाले 6 अवैध निर्माणों की पहचान की है। नगर निगम के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 के बीच हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में करीब 600 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

ममता का राजनीतिक करियर समाप्त : शुभेंदु अधिकारी

❑ भवानीपुर में आयोजित धन्यवाद सभा में मुख्यमंत्री ने जनता का आभार जताया

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर सोमवार को तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि वह अपने ही बूथ तक पर हार गई हैं और राज्य की जनता ने उनके राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया है। इस दिन, शाम को ममता के गृह क्षेत्र व राजनीतिक गढ़ रहे कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा अंतर्गत कैमक स्ट्रीट में भाजपा की ओर से आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने कहा कि जो नेता अपने ही बूथ में जीत नहीं सकता, उसे बंगाल की जनता ने दरवाजा दिखा दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भवानीपुर स्थित मित्रा इंस्टीट्यूशन जहां ममता बनर्जी मतदान करती हैं, वहां के चार बूथों पर भाजपा को बढ़त मिली। शुभेंदु ने जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। जनता ने आपको टाटा-बाय-बाय कर दिया है। शुभेंदु ने राज्य के पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोलकाता के चेतला गर्ल्स स्कूल स्थित मतदान केंद्र, जहां फिरहाद हकीम वोट करते हैं, वहां के पांच बूथों में भी भाजपा को बढ़त मिली। मुख्यमंत्री के मुताबिक, चेतला के बंगाली हिंदुओं ने मुझे 15 हजार वोटों की बढ़त दी है।

'जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित

हुगली : जिला शासक कार्यालय में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर हुगली के जिलाधिकारी खुरशीद अली कादरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी ने बताया कि जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले शीर्षक के तहत 18 मई से 25 मई 2026 तक हुगली जिले के पांच ब्लॉकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महा अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रभावी रूप से लागू करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह पहल मुख्य रूप से कन्वर्जेंस आधारित मॉडल पर संचालित की जाएगी, ताकि आदिवासी समुदाय तक सरकारी सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकतम स्तर तक पहुंचाया जा सके।

कसाईखानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू करने की मांग, कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कसाईखानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी गौवंश को वध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस नियम का कथित रूप से उल्लंघन हो रहा है। मामले में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता बीके शर्मा की ओर से अधिवक्ता मेघनाथ दत्त ने हाईकोर्ट में यह मामला दायर किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की शीघ्र सुनवाई की अपील की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद राज्य के कई कसाईखानों में नियमों की अनदेखी कर गौवंश की हत्या की जा रही है।

याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। अधिवक्ता मेघनाथ दत्त ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के आदेश केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक पालन भी होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया है। हालांकि सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच नहीं बैठने के कारण मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत की ओर से बताया गया कि नियमानुसार इस मामले को नियमित बेंच में स्थानांतरित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, यदि सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो मंगलवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

गुड़ाप में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले व धमकी के आरोप में तीन टीएमसी नेता गिरफ्तार

हुगली : जिले के गुड़ाप थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, धमकी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम शुकदेव महतो, टुटुल दास और देवाशीष घोष है। इनमें शुकदेव महतो धनियाखाली विधानसभा क्षेत्र के गुड़बाड़ी पंचायत तृणमूल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। बाकी दो आरोपित भी इलाके में सक्रिय तृणमूल नेता के रूप में जाने जाते हैं। स्थानीय सूत्रों और पुलिस के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद धनियाखाली क्षेत्र के कई इलाकों में तनाव और हिंसा का माहौल बन गया था। आरोप है कि उस समय तृणमूल नेता और

कार्यकर्ताओं ने कई भाजपा समर्थकों के घरों में घुसकर मारपीट की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि भय के कारण उस समय कोई भी थाने में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कथित पीड़ित भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिम्मत जुटाकर गुड़ाप थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

मतगणना की रात महिला से छेड़छाड़ व पति से मारपीट के आरोप में तृणमूल नेता समेत चार गिरफ्तार

हुगली जिले के मगरा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी किशोरी संघ क्लब के पास मतगणना की रात कथित तौर पर महिला से छेड़छाड़, उसके पति की पिटाई और घर पर हमला करने के मामले में पुलिस ने तृणमूल नेता समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को सभी आरोपितों को चुंचुड़ा अदालत में पेश किया गया। आरोप है कि गत चार मई को इलाके में खु-लेआम शराब और गांजा सेवन का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक परिवार को निशाना बनाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों ने घर में घुसकर हमला किया, हथियारों से मारपीट की तथा उसके साथ अश्लीलता की। हमले में महिला के पति को भी बुरी तरह पीटा गया। इस मामले में गौतम दास उर्फ 'बोलो', जो बीटीपीएस के तृणमूल श्रमिक संगठन के सचिव बताए जाते हैं, को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ तनमय दास, प्रवीर सरकार और सुजीत कुंडू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस पहले ही दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद से गौतम दास समेत चारों आरोपित फरार थे। रविवार रात इलाके में लौटने पर मगरा थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गंगा में छलांग लगाने के बाद लापता हुई किशोरी, तलाश जारी

हुगली : चंदननगर के जोड़ा घाट इलाके में 14 वर्षीय एक किशोरी गंगा नदी में डूब गई। घटना के बाद से उसकी तलाश जारी है। मृतका का नाम कृति साव बताया गया है। उसके पिता का नाम सूरज साव है और वह चंदननगर के कुटीर मठ इलाके की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार, कृति घर से जिम जाने की बात कहकर निकली थी। बाद में वह अपनी दो सहेलियों अलबिरा खातून और मोनिका विश्वास के साथ पैंट खरीदने गई थी। बताया जा रहा है कि तीनों सहेलियां जोड़ा घाट के पास गंगा किनारे बैठी थीं। इसी दौरान अचानक कृति ने नदी में छलांग लगा दी। उसे डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत नदी में कूदकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलने के बाद चंदननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। किशोरी की तलाश के लिए अभियान जारी है।

भ्रष्टाचार के आरोपित तृणमूल नेताओं पर कार्रवाई जारी, कई जिलों में गिरफ्तारियां

दुर्गापुर-फरीदपुर ब्लॉक का तृणमूल अध्यक्ष गिरफ्तार

दुर्गापुर : दुर्गापुर-फरीदपुर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शतद्वीप घटक को पुलिस ने वसूली, आतंक फैलाने और लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रविवार की रात फरीदपुर थाना की पुलिस ने लाउदोहा इलाके में अभियान चलाकर उन्हें हिरासत में लिया। सोमवार की सुबह आरोपित को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने हिरासत की मांग की है। आरोप है कि उनके संरक्षण में लंबे समय से इलाके में भय का माहौल बना हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने, आम लोगों पर दबाव बनाने और चुनाव के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। स्थानीय लोगों ने पहले भी कई बार शिकायत की थी। गिरफ्तारी के बाद शतद्वीप घटक ने दावा किया कि यह कार्रवाई पुराने (2021) मामले में की गई है और इसे राजनीतिक बताया। अदालत ले जाते समय एक व्यक्ति ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए, जिससे कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया।

डराने-धमकाने और जमीन कब्जाने के आरोप में तृणमूल नेता समेत तीन गिरफ्तार

पूर्व बर्दवान : जिले में पुलिस ने लोगों को डराने-धमकाने और जमीन कब्जाने के आरोप में तृणमूल नेता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान तृणमूल जिला सचिव सुब्रत घोष, युवा नेता राजीव दास और उनके एक सहयोगी संजय मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, इन सभी पर इलाके के लोगों को डराने-धमकाने, दबाव बनाने और एक महिला की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपित उस जमीन पर क्लब बनाने की योजना बना रहे थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपितों से पूछताछ जारी है।

दासपुर के पूर्व तृणमूल विधायक का बेटा कुमारेस भुइयां गिरफ्तार

पश्चिम मेदिनीपुर : जिले के दासपुर में पूर्व तृणमूल विधायक ममता भुइयां का बेटा कुमारेस भुइयां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार की देर रात दासपुर थाने की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। कुमारेस भुइयां दासपुर-एक पंचायत समिति के कार्याध्यक्ष हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व विधायक का बेटा होने के कारण इलाके में उनका काफी दबदबा था। उनके खिलाफ जबरन उगाही, गड़बड़ी और अशांति फैलाने में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की दोपहर पुलिस ने कुमारेस को हिरासत में लेकर थाने में लंबी पूछताछ की। इसके बाद, देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि कुमारेस के पिता अजीत भुइयां जिले के प्रभावशाली तृणमूल नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनकी मां ममता भुइयां दासपुर से तीन बार विधायक रह चुकी हैं। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। उनकी जगह आशिष हुडैत को टिकट दिया गया था, जिन्हें भाजपा के तपन दत्ता ने चुनाव में हरा दिया। पता चला है कि कुमारेस पर ठेकेदारों, प्रमोटरों और व्यापारियों से उगाही करने के भी आरोप हैं। इस संबंध में दासपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया गया है कि रविवार को बालिपोता इलाके में कुमारेस के एक दुकान पर पहुंचने पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी की। इसके बाद, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां बाद में गिरफ्तारी की गई।

कूचबिहार में तृणमूल का ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल कादेर गिरफ्तार

कूचबिहार : कूचबिहार में एक प्रभावशाली तृणमूल नेता की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के कूचबिहार एक बी ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल कादेर को पुलिस ने सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कूचबिहार के गुड़ियाहाटी नंबर दो ग्राम पंचायत इलाके से हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दोपहर को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब्दुल कादेर के खिलाफ चुनाव से पहले विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला, घरों में तोड़फोड़, लूटपाट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है।

जबरन वसूली मामलें में मलय घटक का करीबी आईएनटीटीयूसी नेता गिरफ्तार

आसनसोल : आसनसोल शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर दुकान लगाने वालों से हफ्ता वसूली और टोटो-ई रिक्शा चालकों से 'दादा टैक्स' के नाम पर प्रतिदिन पैसे वसूलने के आरोप में एक बड़ा मामला सामने आया है। इस संबंध में सुकांतो मैदान इलाके के निवासी छोटू रावत ने आसनसोल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद टाकिर, मोहम्मद लालू, मोहम्मद अजीज, गौतम दास, अमर नंदी, गुल्लू, विश्वजीत राय और राजू उर्फ अहलूवालिया को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आइएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोप में तृणमूल नेता समेत 3 गिरफ्तार

हुगली : श्रीरामपुर थाना पुलिस ने जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोप में आइएनटीयूसी के एक सचिव समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को श्रीरामपुर अदालत में पेश कर 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। जानकारी के अनुसार, हुगली जिले के श्रीरामपुर इलाके के राज्यधरपुर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 26 में यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि वर्ष 2024 में वेस्ट बंगाल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के कर्मचारी गोबिंद मंडल की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, मिल प्रबंधन ने उनके परिवार को 18 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। मृतक के पुत्र आकाश मंडल का आरोप है कि मुआवजे की राशि दिलाने के नाम पर मिल के कुछ कर्मचारियों और तृणमूल से जुड़े नेताओं ने उससे 6

लाख रुपये की मांग की। आरोप है कि चरणबद्ध तरीके से उससे 25 हजार रुपये की वसूली भी की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक उसे घोषित मुआवज़ा नहीं मिला।

पीड़ित ने बताया कि इस मामले में पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद आकाश मंडल ने दोबारा पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर श्रीरामपुर थाना पुलिस ने आइएनटीयूसी सचिव प्रबीर मंडल, पूर्व सचिव शेख रबियाल और मिल कर्मचारी प्रसेंजित को गिरफ्तार कर लिया।

श्रीरामपुर के डीसीपी अर्नब विश्वास ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली समेत कई गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अदालत से 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

हथियार रखने के आरोप में तृणमूल विधायक का बेटा सहित पांच गिरफ्तार

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव के समय विपक्षी भाजपा के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोपों में घिरे विष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक दिलीप मंडल की तलाश में जुटी पुलिस ने अब उनके पुत्र अर्घ्य मंडल सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आर्घ्य मंडल और अन्य लोगों के पास से हथियार बरामद हुए। ऑपरेशन के दौरान दो पिस्तौल और छह मोबाइल फोन जब्त किए गए। उन पर इलाके में अशांति फैलाने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक, रविवार की रात विधायक के पुत्र की तलाश में राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और डायमंड हार्बर जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान बक्खाली-फ्रेजरगंज इलाके से अर्घ्य मंडल सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।

शोवनदेब चटर्जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दिए जाने में देरी पर दायर करेंगे आरटीआई

कोलकाता, समाज्ञा

तृणमूल कांग्रेस विधायक शोव-नदेब चट्टोपाध्याय ने सोमवार को कहा कि वह राज्य की 18वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आवेदन दाखिल करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक संख्या बल होने के बावजूद उनकी पार्टी को उसका हक नहीं दिया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि तृणमूल ने अपने विधायक दल के नेता का नाम बताते हुए पत्र तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन संबंधित दस्तावेज अभी तक नहीं दिए गए हैं। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों ने तृणमूल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि यह पत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के 'लेटरहेड' पर भेजा गया था। विधायक चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि उन्होंने तृणमूल के 80 विधायकों के समर्थन से अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता चुने जाने की सूचना विधानसभा अध्यक्ष रतिनाथ बसु को दे दी गई है, लेकिन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पांच दिन बाद भी उन्हें औपचारिक मान्यता नहीं दी गई है। विधायक ने पत्रकारों से कहा कि मैं एक आरटीआई दाखिल करुंगा। मैंने विधानसभा में 2011, 2016 और 2021 में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रियाओं का विवरण मांगा है।

तपसिया में सड़क हादसे में एक की मौत, चार घायल

कोलकाता, समाज्ञा : महानगर के तपसिया इलाके में सोमवार की सुबह एक सड़क हादसे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चार नंबर पुल से साइंस सिटी की ओर जा रही थी। आरोप है कि बस तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान उसने पहले सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को टक्कर मारी और फिर एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े। घायलों को तुरंत नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हादसे में शामिल बस को जब्त कर लिया है। मामले की जांच के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

बाली के विकास और भयमुक्त माहौल पर होगा फोकस : विधायक संजय सिंह

हावड़ा : बाली के विधायक संजय सिंह ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों, जल निकासी, ट्रैफिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बाली लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है और अब प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं के समाधान के लिए काम शुरू कर दिया गया है। संजय सिंह ने दावा किया कि क्षेत्र में अब भय और असुरक्षा का माहौल खत्म हो रहा है तथा विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर लगातार पहल की जा रही है।

❑ हावड़ा के बाली क्षेत्र से चुनाव लड़ने के पीछे क्या वजह रही?

पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताते हुए बाली से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और संगठन जहां जिम्मेदारी देता है, वहां पूरी निष्ठा के साथ काम करना मेरा कर्तव्य है। बाली की जनता ने मुझे अपना समर्थन और प्यार दिया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करूं।

❑ बाली में आपने कई समस्याएं देखी होंगी। सबसे पहले किस मुद्दे पर काम करना चाहेंगे?

– सबसे पहले बाली को भयमुक्त बनाना जरूरी था। यहां लंबे समय से तृणमूल द्वारा लोगों में डर और अस-ुरक्षा का माहौल बनाया जाता था। अब स्थिति में बदलाव आया है और लोग खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं। आगे हमारा मुख्य फोकस विकास कार्यों को गति देना है।

❑ दो ऐसे प्रमुख काम बताइए, जिन्हें आप प्राथमिकता के तौर पर करना चाहते हैं?

–बाली में जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है। पिछले सात दिनों से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। केएमडीए, सिंचाई विभाग, बाली नगरपालिका और हावड़ा नगर निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी के साथ प्रशासनिक बैठक भी हो चुकी है और काम शुरू हो गया है।

दूसरी बड़ी समस्या ट्रैफिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की है। इलाके में अस्पतालों की स्थिति काफी खराब है। इस संबंध में आयुष मंत्रालय से बातचीत की जा रही है और आगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

❑ क्षेत्र के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आपकी क्या योजना है?

हमारी कोशिश रहेगी कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। लोगों को योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं आसानी से मिलें, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जाएंगे।

❑ अपने शुभचिंतकों और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे?

मैं बाली की जनता का धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए वही सच्चे शुभचिंतक हैं, जो क्षेत्र के विकास और लोगों की भलाई के लिए सकारात्मक सहयोग करें। हम सभी को मिलकर बाली को बेहतर और विकसित क्षेत्र बनाना है।

राज्य चिकित्सा परिषद से हटाए गए पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल माजी

कोलकाता, समाज्ञा : तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल माजी को पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद में उनके पद से हटा दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। यह फैसला राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की कोशिशों के बीच लिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को एसएसकेएम अस्पताल में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अस्पतालों के निदेशक और अधीक्षक मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं के कामकाज में सुधार के लिए बैठक में कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने विभाग में मौजूद 'अनियमितताओं को खत्म करने' की जरूरत पर जोर दिया। राज्य चिकित्सा परिषद से सदस्यों को हटाने का फैसला इसी बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। आदेश में कहा गया कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद के नामित सदस्य डॉ. निर्मल माजी का कार्यकाल 11 मई की दोपहर से समाप्त किया जाता है।

श्रम संगठनों ने सिर्फ 'सत्यानाश' ही किया : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम संगठनों की कड़ी आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि इन संस्थाओं का रवैया कभी सकारात्मक नहीं रहा और उन्होंने सिर्फ 'सत्यानाश' ही किया है। आदित्यनाथ ने एक प्रमुख हिंदी दैनिक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रम संगठनों को जमकर खरी-खोटी सुनायी। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग क्षेत्र का व्यक्ति, अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करता है, लेकिन कभी-कभी उसके स्वर ट्रेड यूनियन जैसे हो जाते हैं।' उन्होंने कहा, 'ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति कभी सकारात्मक नहीं रही। इसने सत्यानाश ही किया है। ये चंदा वसूली और 'अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम' की तर्ज पर पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का काम करती हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'ट्रेड यूनियन के नेता कोई काम नहीं करते, कंधे पर झोला लटकाए घूम-घूम कर डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। चंदा वसूली से अपना घर भरते हैं और श्रमिकों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं।' आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि श्रम संगठनों के नेता सांसद व मंत्री बन गए लेकिन श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गया।

बिहार के सासाराम में ट्रेन के डिब्बे में लगी आग, कोई हताहत नहीं

पटना: बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार तड़के ट्रेन के एक खाली डिब्बे में आग लग गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सुबह पांच बजकर 30 मिनट पर सासाराम-पटना सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या छह पर खड़ी थी, तभी उसके एक डिब्बे से धुआं निकलता देखा। उन्होंने कहा, 'रेलवे अधिकारियों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।'

तीन बच्चों को आग से बचाने वाली मां खुद को ना बचा सकी

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटना लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में संगम नगरी में आग लगने की एक ऐसी घटना घटी जिसमें मां ने अपने तीन बच्चों को तो किसी तरह से बचा लिया, लेकिन वह खुद को नहीं बचा सकी। सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत की छत पर फंसी महिला करीब आधे घंटे तक आग के धुंए से अपने तीन बच्चों को निकालने के लिए संघर्ष करती रही। सबसे पहले उसने अपने एक साल के बच्चे को एक चादर में लपेटा और पड़ोसियों को सौंपा।

गोरखपुर में नाले में मिला युवक का शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

गोरखपुर (उप्र): उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के फरेना नाले में सोमवार सुबह एक युवक का शव तैरता मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 5:30 बजे मोतीराम अड्डा इलाके में बंजारी पुल के पास स्थानीय लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान चौरी चौरा के अवधपुर दारोगा जी छावनी निवासी लाल बहादुर निषाद (32) के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिवार का आरोप है कि लाल बहादुर की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि शव पर फिलहाल कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं।

पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता तीन गुना बढ़ा, अब मिलेंगे 12,000 रुपये प्रतिमाह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को तीन गुना बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में भत्ते को 4,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया गया। दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पशुधन की बड़ी संख्या और अर्थव्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पशु चिकित्सकों की जिम्मेदारी काफी अहम है। उन्होंने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण, महामारियों के नियंत्रण और उन्नत नस्लों के संवर्धन में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ भत्ता उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को मिलेगा।

गंगा में इफ्तार पार्टी करने के शेष छह आरोपियों को भी जमानत मिली

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी करने और मांसाहार कर हड्डियां फेंकने के शेष छह आरोपियों को भी सोमवार को जमानत दे दी। इससे पूर्व 15 मई को अदालत ने 14 में से आठ आरोपियों को जमानत दे दी थी। शेष छह आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने कहा, इसी अपराध में आठ आरोपियों को 15 मई को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए मौजूदा याचिकाकर्ता भी जमानत पाने के पात्र हैं। इससे पहले, न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने 15 मई को मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल आफरीदी, मोहम्मद तौसीफ अहमद और मोहम्मद अनस को यह कहते हुए जमानत प्रदान की थी कि ये आरोपी 17 मार्च, 2026 से जेल में निरुद्ध हैं और इन्होंने पछतावा जताते हुए भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं करने का वादा किया है। इसी मामले में, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने उसी दिन (15 मई) तीन आरोपियों मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान को जमानत दी थी।

न्यूज अपडेट

राज्यपाल बागडे ने राजस्थान विधानसभा के प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया

जयपुर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवनिर्मित प्रतीक चिन्ह (लोगो) का विमोचन किया। उन्होंने इस दौरान विधानसभा के विभिन्न 13 द्वारों का भी नामकरण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का गौरवमय इतिहास रहा है। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी की पहल पर तैयार 'लोगो' राजस्थान के जन मानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने प्रतीक चिन्ह में सम्मिलित राज्य पुष्प रोहिडा, खेजड़ी और विधानभवन की छवियों की चर्चा करते हुए कहा कि यह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्सवधर्मिता से जीवन जीने वाले लोगों की जीवटता को दर्शाता है। बागडे ने कहा कि जीवन में आदर्श आचरण के साथ सभी चीजों का प्रबंधन व्यवहार में आना जरूरी है। उन्होंने पिछड़े और गरीब लोगों की शिक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश शिक्षा से ही आगे जाता है। वहां के बच्चों की प्रतिभा से जाता है। शिक्षा को व्यवहार में लाने की जरूरत है। सभी स्कूल अच्छे कैसे हों। वहां व्यवहारिक शिक्षा कैसे मिले, इस पर सभी मिलकर ध्यान दें। राज्यपाल ने महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष रहने के अपने संस्मरण भी साझा किए और कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम अधिकारों के साथ कर्तव्य के प्रति भी सजग रहें।

लखनऊ में एसजीपीजीआई में भर्ती मरीज का खून से लथपथ गला कटा शव बरामद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती एक मरीज का सोमवार तड़के खून से लथपथ शव बरामद किया गया, जिसका गला कटा हुआ था। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमित कुमार आनन्द ने पत्रकारों को बताया कि मृतक की पहचान बस्ती जिले के निवासी मुश्ताक अली (61) के रूप में हुई जो लीवर कैंसर से पीड़ित था। डीसीपी ने बताया कि सोमवार को पीजीआई थाना क्षेत्र में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती बस्ती जिले के निवासी एक मरीज मुश्ताक अली (61) की गला कटने से मौत की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। आनन्द ने बताया कि पूछताछ में यह पता चला कि करीब चार-साढ़े चार बजे उसके बगल के बेड पर भर्ती मरीज के तीमारदार ने देखा कि मुश्ताक के गले से खून निकल रहा है, तत्काल सूचना स्टाफ एवं पुलिस को दी गई। डीसीपी ने बताया कि उसके बगल में एक ब्लेड पड़ा था और वह पिछले एक माह से पीजीआई में भर्ती था। उन्होंने कहा कि वह लीवर कैंसर से ग्रसित था और लगभग आठ-नौ माह से उपचाराधीन था। उन्होंने यह भी बताया कि वह आर्थिक तंगी में भी था। डीसीपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

नीट-यूजी परीक्षा फिर से आयोजित होने की घोषणा के बाद छात्र पढाई के लिए कोटा लौट रहे

कोटा: भारत की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) देने के बाद कोटा से अपने घर लौट चुके विद्यार्थी मजबूरी में अब फिर छात्रावास लौटने लगे हैं। ये विद्यार्थी इस उम्मीद में बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर लौट चुके थे कि अब उन्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न-पत्र लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा की घोषणा के साथ ही उन्होंने फिर से कोटा का रुख कर लिया है तथा अब फिर से छात्रावास गुलजार होने लगे हैं। ऐसी ही एक छात्रा अनामिका वर्मा लखनऊ से वापस छात्रावास पहुंची है और आज उसने अपने कमरे को फिर से व्यवस्थित किया। उसने कहा, ''नीट-यूजी परीक्षा के बाद मैं लखनऊ वापस चली गई थी, लेकिन कोटा लौट आई, क्योंकि घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती... वहां पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता।'' अनामिका की तरह कई मेडिकल छात्र धीरे-धीरे देश की 'कोचिंग राजधानी' कोटा की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को इसे फिर से कराने की घोषणा की है।

सरकार का लक्ष्य लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना : सम्राट

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार से बाहर रह रहे लोगों से राज्य में लौटकर उद्योग स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश को समृद्ध बनाने में सभी की भूमिका होनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और सरकार का लक्ष्य लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बिहार आ रहे हैं और सरकार का लक्ष्य 20 नवंबर 2026 तक राज्य में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित करना है। सम्राट ने यह बात 80 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को हरी झंडी दिखाने और एआई आधारित आधुनिक दमकल नियंत्रण कक्ष के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है तथा गया में भी ऐसा केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अधिक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे परियोजनाओं की लागत में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस को पूरी छूट दी गई है और बिहार को सुशासन वाला राज्य बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार से सभी पंचायतों में 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम शुरू होगा, जहां प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निपटारा अनिवार्य होगा।

यूपी पुलिस ने नौ वर्ष में 289 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया; 34,253 गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति के तहत सतत कार्रवाई करते हुए पिछले नौ वर्षों में 289 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, इस अवधि में पुलिस के साथ मुठभेड़ की कुल 17,043 घटनाएं हुईं, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें बताया गया है कि इन मुठभेड़ में कुल 11,834 अपराधी घायल हुए। इस दौरान अपराधियों से मोर्चा लेते वक्त 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। बयान में कहा गया है कि मुठभेड़ की सबसे अधिक 4,813 घटनाएं मेरठ ज़ोन में हुईं। इस कार्रवाई में 8,921 अपराधी दबोचे गये और 3,513 अपराधी घायल हुए, जबकि 97 कुख्यात अपराधी मौके पर ही मारे गये। बयान के अनुसार, मेरठ जोन में हुई मुठभेड़ के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये। इसी तरह, वाराणसी जोन में मुठभेड़ की 1,292 घटनाएं हुईं, जिनमें 2,426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 29 अपराधी ढेर कर दिये गये। इस दौरान 907 अपराधी और 104 पुलिसकर्मी घायल हुए। बयान के मुताबिक, आगरा जोन में मुठभेड़ की 2,494 घटनाएं हुईं, जिनमें 5,845 अपराधी दबोचे गये। इस दौरान 968 अपराधी घायल हुए, जबकि 24 अपराधी मार गिराए गए। मुठभेड़ के दौरान 62 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मुठभेड़ के आंकड़ों पर नजर डालें तो बरेली ज़ोन में 2,222 मुठभेड़ के दौरान 21 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए, जबकि लखनऊ ज़ोन में 971 मुठभेड़ के दौरान 20 अपराधी मारे गए। गाजियाबाद कमिश्नरी में 7,89 मुठभेड़ में 18 अपराधी मारे गये। बयान के मुताबिक, कानपुर जोन में 791 मुठभेड़ में 12, लखनऊ कमिश्नरी में 147 मुठभेड़ में 12 तथा प्रयागराज जोन में 643 मुठभेड़ में 11 अपराधियों को ढेर किया गया। इसी तरह आगरा कमिश्नरी में 489 मुठभेड़ में 10, गौतमबुद्ध नगर में 1,144 मुठभेड़ में नौ, गोरखपुर जोन में 699 मुठभेड़ में आठ, वाराणसी कमिश्नरी में 146 मुठभेड़ में आठ, प्रयागराज कमिश्नरी में 150 मुठभेड़ में छह और कानपुर कमिश्नरी में 253 मुठभेड़ों में चार अपराधियों को ढेर किया गया।

समाग्या धर्म-अध्यात्म

व्रत - त्यौहार

20.05.2026 : वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत
25.05.2026 : रोहिणी के सूर्य रात 8:21

मुश्किल समय में इंसान को मजबूत बनाती हैं गीता की ये बातें

कहते हैं कि, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें बताई हैं, जो हर इंसान को कठिन समय में सही राह दिखाने का काम करती हैं। गीता के अनुसार, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को हमेशा धैर्य, अच्छे कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि, हजारों साल बाद भी गीता में कही गई बातें आज के समय में उतनी ही सच्ची और प्रभावशाली मानी जाती हैं। मान्यता है कि, जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इस दौरान गीता में मौजूद इन मुख्य बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इससे व्यक्ति जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है।

मान्यताओं के अनुसार, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसे उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि, जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और लालच के पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करता है, तब सफलता स्वयं उसके पास आती है।

गीता के अनुसार, व्यक्ति को समय-समय पर खुद को समझना चाहिए और अपनी गलतियों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है।

श्रीकृष्ण के अनुसार, जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, धन, शक्ति या सफलता पर घमंड होने लगता है, तब उसका विवेक धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। अहंकार इंसान की सोचने-समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है और यही उसके पतन का कारण बनता है।

समय कैसा भी हो, व्यक्ति को हमेशा सही और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। गलत रास्ते से मिली सफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, जबकि अच्छे कर्म और ईमानदारी इंसान को जीवनभर सम्मान दिलाते हैं।

भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वह बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को भी आसानी से पार कर सकता है। क्रोध, लालच और नकारात्मक विचार इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं।

गीता में बताया गया है कि, जीवन में सुख और दुख हमेशा आते-जाते रहते हैं। कठिन समय देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धैर्य और आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति ही जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार करने में सफल हो पाता है।

शुरू हुआ अधिकमास, इन कार्यों से रहें दूर वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

हिंदू धर्म में अधिक मास को बेहद पुण्यदायी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर समय माना जाता है। आज से शुरू हो रहा यह पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूजा-पाठ, दान, जप और तप करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हालांकि, इस पूरे महीने में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास आत्मचिंतन, भक्ति और धर्म-कर्म के जरिए जीवन में सकारात्मकता लाने का विशेष अवसर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्यों खास माना जाता है और इस दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है।

तीन साल में एक बार आता है अधिक मास

अधिक मास हर तीन साल में एक बार इसलिए आता है क्योंकि हिंदू पंचांग की गणना सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति के आधार पर की जाती है। सौर वर्ष करीब 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों में पूरा हो जाता है। ऐसे में दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। यही अंतर धीरे-धीरे बढ़ते हुए करीब तीन साल में एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। पंचांग और ऋतु चक्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए, इस अतिरिक्त समय को एक अलग महीने के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता, इसलिए इसे पहले मलमास कहा जाता था। बाद में भगवान विष्णु ने इसे अपना प्रिय और पवित्र महीना घोषित किया, जिसके बाद इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। तभी से इस महीने को पूजा-पाठ, जप, तप और दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है।

भूलकर भी न करें ये काम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास को भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का महीना माना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान ऐसे कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं या सांसारिक दिखावे से जुड़े हों। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पूरे महीने व्यक्ति को अपने व्यवहार, खानपान और दिनचर्या में विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार और तिलक जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस समय किए गए शुभ कार्य अपेक्षित फल नहीं दे पाते, इसलिए इन्हें टालना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा नया कारोबार शुरू करना, नई संपत्ति या वाहन खरीदना भी इस अवधि में शुभ नहीं माना गया है।

खानपान को लेकर भी इस महीने खास नियम बताए गए हैं। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब और अन्य नशीली चीजों से दूरी बनाकर सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह समय मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखने का माना गया है।

शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अधिक मास के दौरान क्रोध, झूठ, चुगली, विवाद और किसी का अपमान करने जैसी आदतों से बचना चाहिए। इस महीने में अच्छे विचार, शांत व्यवहार और भगवान के नाम का स्मरण व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है।

अधिक मास में क्या करें

अधिक मास में पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने नियमित रूप से दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की उपासना को सबसे फलदायी माना गया है। प्रतिदिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।

दान का भी अधिक मास में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करने से जीवन के कई कष्ट दूर होते हैं। शास्त्रों में कांसे के पात्र में मालपुए रखकर दान करने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है, जिसे बेहद शुभ माना गया है।

अधिक मास के दौरान सात्विक और संयमित जीवन जीने पर भी जोर दिया गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मन को शांत रखना, ईश्वर का ध्यान करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने किए गए अच्छे कर्म कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं।

शादी के पहले 5 कार्ड इन देवी-देवताओं को करें

हिंदू धर्म में शादी-विवाह का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह न सिर्फ एक रिश्ता, बल्कि पवित्र संस्कार माना जाता है। शास्त्रों में शादी और उससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी रस्म का खास महत्व बताया गया है। इन्हीं परंपराओं में एक शादी के निमंत्रण कार्ड को लेकर भी शामिल है। कहा जाता है कि, विवाह का पहला कार्ड देवी-देवताओं को अर्पित करने से सभी तरह की बाधाएं समाप्त होती हैं और नवदंपति को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आमतौर पर लोग पहला निमंत्रण भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ अन्य देवी-देवताओं को भी निमंत्रण देना शुभ होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

पहला निमंत्रण भगवान गणेश को

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शादी का पहला कार्ड भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। वह इसके उनके आशीर्वाद से विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। यही नहीं सभी मांगलिक कार्य बिना किसी परेशानी के पूर्ण होते हैं।

दूसरा निमंत्रण भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को

शादी का दूसरा निमंत्रण कार्ड भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को देना चाहिए, क्योंकि वह सुख, समृद्धि और वैवाहिक खुशहाली के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से दांपत्य जीवन में हमेशा सुख-शांति बनी रहे।

तीसरा निमंत्रण हनुमान जी को

मान्यता है कि, हनुमान जी की कृपा से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और मन निडर बनता है। ऐसे में विवाह का तीसरा कार्ड बजरंगबली को अर्पित करना चाहिए। यह बुरी नजरों से भी बचाव करता है।

चौथा निमंत्रण कुलदेवी या कुलदेवता को

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म में हर परिवार के अपने कुलदेवता या कुलदेवी होते हैं। ऐसे में घर में विवाह जैसे मांगलिक कार्य में उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद शुभ होता है। इससे परिवार पर कृपा बनी रहती है और नए रिश्ते में खुशियां आती हैं। इसलिए चौथा निमंत्रण कुलदेवी या कुलदेवता को अवश्य दें।

पांचवां निमंत्रण पितरों को

शादी का एक निमंत्रण पितरों को अवश्य देना चाहिए। उनकी कृपा वंश पर बनी रहती है और घर में सभी कार्य बिना किसी परेशानी के पूर्ण होते हैं। इसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे कार्ड रखें।

न्यायालय ने उमर खालिद, शरजील इमाम को जमानत से मना करने के पूर्व के फैसले पर उठाए सवाल

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार के पांच जनवरी के अपने फैसले पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि ''जमानत नियम है तथा जेल अपवाद'' और यह महज खोखला वैधानिक बयान नहीं है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ द्वारा दिए गए तर्क पर उसे ''गंभीर आपत्ति'' है। पांच जनवरी को, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारी की पीठ ने खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे गवाहों की गवाही के एक वर्ष बाद नयी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।

पांच नाबालिगों ने संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को जासूसी में मदद की :एनआईए

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी षड्यंत्र से संबंधित मामले में पांच नाबालिगों के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की। अधिकारियों ने बताया कि इस षड्यंत्र में भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से आरोपियों पर संवेदनशील स्थानों की जासूसी करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कौशांबी पुलिस थाने में मार्च में दर्ज किए गए जासूसी मामले में अब तक कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर रेलवे स्टेशनों के संवेदनशील स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले कैमरे लगाने और उनसे पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकवादियों को सीधे जानकारी उपलब्ध कराने का आरोप है। एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि पुलिस से जांच का जिम्मा लेने के बाद, एनआईए ने पाया कि पांचों नाबालिगों ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालते हुए संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को संवेदनशील प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और वीडियो, साथ ही उनके सटीक जीपीएस निर्देशांक प्राप्त करने में सहायता की।

ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली और गोवा में छापेमारी के बाद कथित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिंगला दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र से आप के उम्मीदवार थे। ईडी ने 2024 में भी जांच के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा था। धन शोधन का यह मामला बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने के बाद सिंगला को गिरफ्तार किया गया।

सड़कों पर नमाज पर रोक के फैसले का विहिप ने किया स्वागत

नयी दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ की गई कार्रवाई का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि सड़कें आवागमन और आम लोगों की सुविधा के लिए होती हैं। विहिप की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारों द्वारा सड़क किनारे नमाज अदा करने पर रोक लगाने के फैसले के बाद आई है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर मजबूत संदेश दिया है कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, सड़कों पर नमाज पढ़ना एक विशेष समुदाय द्वारा शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया था, लेकिन अब इसे और अधिक कड़ाई से लागू किया जा रहा है क्योंकि कुछ स्थानों पर सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था। बंसल ने आरोप लगाया कि शुक्रवार, ईद और अन्य अवसरों पर सड़कों पर नमाज अदा किए जाने से आम लोगों को परेशानी होती है और यातायात प्रभावित होता है। उन्होंने कहा, कुछ स्थानों पर तो एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती हैं। बंसल ने पश्चिम बंगाल में उठाए गए कदमों का भी स्वागत किया और उम्मीद जताई कि सड़कें यात्रियों और आम जनता के उपयोग के लिए सुगम बनी रहेंगी।

भारत-स्वीडन ने प्रौद्योगिकी और व्यापार साझेदारी को दी नई दिशा

मोदी के स्वीडन दौरे में एआई, 6जी, क्वांटम तकनीक और व्यापार दोगुना करने पर सहमति

गोथनबर्ग (स्वीडन): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान भारत और स्वीडन ने रणनीतिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए व्यापक खाका पेश किया। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 6जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, महत्वपूर्ण खनिज, नवाचार और व्यापार जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। गोथनबर्ग में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया। बैठक में स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया भी मौजूद रहीं। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। मोदी ने इसे भारत-स्वीडन मित्रता का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा लेकर आई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए 2026-2030 के लिए संयुक्त कार्ययोजना अपनाई है। यह योजना आर्थिक एवं सुरक्षा लचीलापन, उभरती प्रौद्योगिकियां, विश्वसनीय कनेक्टिविटी और सतत विकास पर आधारित होगी। दोनों देशों ने भारत-स्वीडन संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत डिजिटल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने और एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, 6जी और क्वांटम तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। साथ ही भारत-स्वीडन टेक्नोलॉजी एवं एआई कॉरिडोर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे उद्योग, स्टार्टअप और शोध संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने व्यापार सुविधा तंत्र, बौद्धिक संपदा अधिकारों और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन को भी दोहराया।

शाह ने अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा - जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अपने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित अमर वाटिका में एक हजार से अधिक शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले एक हजार से अधिक शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शाह ने इस अवसर पर कहा, ''बस्तर की धरती पर शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में हमारे जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करने और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवान कालेन्द्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिजनों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों के बीच बैठकर उनका दुख साझा किया, ढांढस बंधाया तथा सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। शाह ने सुरक्षाबलों के जवानों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके साहस एवं समर्पण की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

महाराष्ट्र के पालघर में सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार को सगाई समारोह में जा रहे मेहमानों से भरा एक टेम्पो मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक से टकरा गया जिसके कारण 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हादसा दहानू तालुका के धानीवारी गांव के पास शाम करीब चार बजे हुआ जब 50 से अधिक यात्री एक आइशर टेम्पो में सवार होकर बापूगांव खड़कीपाड़ा गांव के निवासी बालाराम जयराम दांडेकर नामक व्यक्ति के सगाई समारोह में जा रहे थे। कासा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अमर पाटिल ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, भीषण हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई और 20 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को कासा उप जिला अस्पताल और आसपास के अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो व कंटेनर दोनों पलट गए और कई यात्री वाहनों के नीचे फंस गए। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि टेम्पो में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे और तेज रफ्तार, सड़क का संकरा हिस्सा और टेम्पो चालक द्वारा वाहन पर से नियंत्रण खो देना हादसे के मुख्य कारण माने जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पांच यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि छह अन्य ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, लिहाजा मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के बाद व्यस्त राजमार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय निवासी, पुलिसकर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को केजरीवाल, अन्य आप नेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके साथ-साथ उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में भी सुनवाई होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष सूचीबद्ध है, जबकि अवमानना मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की पीठ द्वारा की जानी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक, संजय सिंह एवं सौरभ भारद्वाज सहित आप के अन्य नेताओं के खिलाफ आबकारी नीति मामले के संबंध में उनके खिलाफ 'अपमानजनक' सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

मोहन माझी सरकार ओडिशा को विकास की नयी ऊंचाइयों पर ले जा रही है : भाजपा अध्यक्ष नवीन

भुवनेश्वर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि मोहन चरण माझी सरकार के नेतृत्व में ओडिशा विकास की नयी ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राज्य के अपने पहले दौरे पर रविवार रात को यहां पहुंचे नवीन ने सोमवार को भुवनेश्वर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा की राज्य कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया, जिसमें संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में, दो इंजन वाली सरकार ओडिशा को विकास की नयी ऊंचाइयों पर ले जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने पंचायत चुनावों से पहले पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए आयोजित खुर्दा जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लिया। भुवनेश्वर के बाहरी इलाके जटनी में प्रशिक्षण शिविर के हिस्से के रूप में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद, नवीन ने कहा, यह आयोजन संगठन की वैचारिक यात्रा को प्रदर्शित करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के कल्याणकारी कार्यों और उपलब्धियों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में ओडिशा में किए गए विकासात्मक प्रयासों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, यह प्रदर्शनी सार्वजनिक सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है और श्रमिकों को नयी ताकत और दिशा प्रदान करेगी। ओडिशा में भाजपा सरकार 12 जून को दो साल पूरे कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करते हुए नवीन ने कहा, हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनसेवा की अवधारणा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। जटनी की अपनी यात्रा के दौरान, नवीन ने पार्टी के प्रशिक्षण शिविर स्थल, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी में 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ओडिशा के मुख्यमंत्री माझी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ नवीन ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया।

तीन मासूमों को जिंदगी देकर खुद आग में समा गई मां

प्रयागराज में दिल दहला देने वाली घटना, धुएं और लपटों के बीच आधे घंटे तक बच्चों को बचाने के लिए लड़ती रही अर्चना

कॉपी : प्रयागराज : मां की ममता कितनी बड़ी होती है, इसका दर्दनाक और भावुक उदाहरण प्रयागराज में देखने को मिला, जहां एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों में घिरे घर से अपने तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद जिंदगी की जंग हार गई। नैनी इलाके के पुराने बाजार स्थित चैंपियन गली में 12 मई को लगी आग ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। नीचे बनी क्रॉकरी की दुकान में अचानक आग लगी और देखते ही देखते लपटें ऊपर बने मकान तक पहुंच गईं। चारों ओर धुआं और चीख-पुकार मच गई। मकान की छत पर फंसी 38 वर्षीय अर्चना केसरवानी करीब आधे घंटे तक मौत से जूझती रही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि अर्चना ने सबसे पहले अपने एक साल के मासूम को चादर में लपेटकर नीचे खड़े लोगों की ओर बढ़ाया, ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद पड़ोसियों ने दो इमारतों के बीच सीढ़ी लगाई, जिसके सहारे अर्चना ने अपनी दोनों बेटियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लेकिन तब तक आग और धुएं ने अर्चना को पूरी तरह घेर लिया था। दमकल कर्मियों ने जब आग पर काबू पाया, तब वह अचेत अवस्था में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नैनी फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी महंतू चौधरी ने बताया कि मकान में ऊपर जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि अर्चना ने आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की और मां होने का सबसे बड़ा फर्ज निभाया।इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जिसने भी यह मंजर देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। अर्चना अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए दिया गया उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।

केरल के 20 मंत्रियों में से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले, 15 करोड़पति : एडीआर की रिपोर्ट

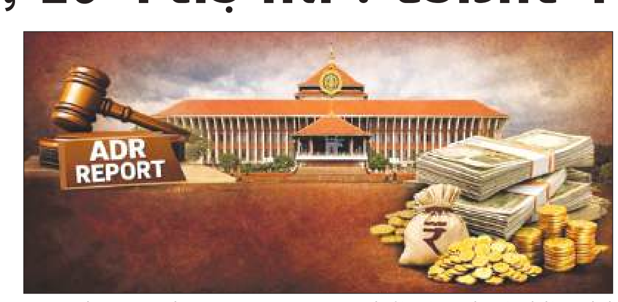

नयी दिल्ली: चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) और 'केरल इलेक्शन वॉच' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के जिन 20 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, उनमें से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन 20 मंत्रियों में से 15 करोड़पति हैं। यह विश्लेषण केरल में 10 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सत्ता में वापसी के बाद, सोमवार को शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सहित 21 मंत्रियों में से 20 के चुनावी हलफनामों पर आधारित है। एडीआर ने कहा कि मंत्री सी पी जॉन के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट तैयार करते समय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया दस्तावेज स्पष्ट नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण किये गए मंत्रियों में से 18, यानी 90 प्रतिशत, ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी दी है। इनमें से 14, यानी 70 प्रतिशत, गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। संपत्ति के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण किये गए 20 मंत्रियों में से 15, यानी 75 प्रतिशत, करोड़पति हैं। इन 20 मंत्रियों की औसत संपत्ति 6.32 करोड़ रुपये की है। रिपोर्ट के अनुसार, चावरा विधायक शिबू बेबी जॉन ने 24.63 करोड़ रुपये की सबसे अधिक संपत्ति घोषित की है, जबकि कोडुंगल्लूर विधायक ओ जे जनीश ने 57.08 लाख रुपये की सबसे कम संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता और आयु संबंधी विवरण का भी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि तीन मंत्रियों (यानी 15 प्रतिशत) की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा के बीच है, जबकि 17 मंत्रियों (यानी 85 प्रतिशत) की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे ऊपर की है। आयु के संदर्भ में, छह मंत्री (यानी 30 प्रतिशत) 31-50 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि 14 मंत्रियों (यानी 70 प्रतिशत) ने अपनी आयु 51 से 80 वर्ष के बीच बताई है। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिमंडल के 21 सदस्यों में से केवल दो महिलाएं हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत है।

ईडी ने दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची, उसके परिजनों से जुड़ी 700 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता था इकबाल मिर्ची

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े एक मामले में मुंबई के वर्ली स्थित तीन प्रमुख इमारतों समेत 700.27 करोड़ रुपये मूल्य की उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के वर्ली स्थित राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा दुबई में स्थित लगभग 203.27 करोड़ रूपये मूल्य की विदेशी संपत्तियों को भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, यह कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा इकबाल मोहम्मद मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम, टाडा (आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और मादक पदार्थ पर रोकथाम से संबंधित 'एनडीपीएस' अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि मिर्ची संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी, रंगदारी वसूली और अवैध हथियारों से जुड़ी गतिविधियां शामिल थीं। मिर्ची ब्रिटेन भाग गया था। जांच एजेंसी ने कहा कि धन शोधन जांच से पता चला है कि इन गतिविधियों के माध्यम से अपराध की आय का कथित तौर पर मिर्ची द्वारा नियंत्रित परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और कंपनियों-संगठनों के नाम पर भारत और विदेश में संपत्तियों की खरीद के नाम पर इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि जांच में पता चला है कि सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट से संबंधित वर्ली की संपत्तियां 1986 में रॉकसाइड एंटरप्राइजेज के माध्यम से 6.5 लाख रुपये में खरीदी गई थीं और कागजों पर संपत्तियां ट्रस्ट के नाम पर होने के बावजूद वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण कथित तौर पर मिर्ची और उनके परिवार के पास ही रहा। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने मिर्ची के साथ मिलकर अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और पिछली कुर्की कार्यवाही से संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी माना जाने वाला और 1993 के मुंबई के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आरोपी इकबाल मिर्ची की 14 अगस्त 2013 को लंदन में 63 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।

नीट पेपर लीक मामले में लातूर के कोचिंग सेंटर का संस्थापक गिरफ्तार

नयी दिल्ली : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक (नीट यूजी) प्रश्नपत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के संस्थापक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेणुकाई केमिस्ट्री सेंटर (आर-सीसी) के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को रविवार शाम गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने रविवार को मोटेगांवकर के आवास की तलाशी ली थी और उस दौरान मेडिकल प्रवेश परीक्षा का लीक हुआ प्रश्न पत्र उसके मोबाइल फोन से मिला। इसके बाद मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मोटेगांवकर नीट यूजी प्रश्नपत्र को लीक करने और प्रसारित करने में शामिल संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था। मोटेगांवकर के कोचिंग सेंटर की लातूर स्थित मुख्य शाखा सहित नौ शाखाएं हैं। सीबीआई ने गिरफ्तारी के अपने आधारों में कहा है कि अन्य आरोपियों के साथ, मोटेगांवकर को परीक्षा से दस दिन पहले 23 अप्रैल को प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि सीबीआई जब्त किए गए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजेगी ताकि यदि कोई डेटा मिटाया गया हो तो उसे पुन: प्राप्त किया जा सके। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने लीक हुए प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां हस्तलिखित नोट्स के रूप में कई लोगों को उपलब्ध कराई थीं, जिन्हें परीक्षा होने के बाद नष्ट कर दिया गया था। एक सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में कहा, वह एनटीए से संबद्ध रसायन विज्ञान के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी का करीबी है। उसके संस्थान और आवास पर तलाशी के दौरान रसायन विज्ञान के प्रश्नपत्र बरामद हुए, जिनमें तीन को आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे।

डब्ल्यूपीएल की टीम का भी मालिक बनना चाहता है पंजाब किंग्स

नयी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भले ही महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का तत्काल विस्तार नहीं करना चाहता हो, लेकिन आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के सह-मालिक मोहित बर्मन का कहना है कि फ्रेंचाइजी उस सत्र पुराने इस टूर्नामेंट में किसी समय एक टीम का मालिक बनना पसंद करेगी। वर्तमान में डब्ल्यूपीएल में आईपीएल फ्रेंचाइजी के स्वामित्व वाली तीन टीम मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स हैं। बीसीसीआई की मौजूदा पांच टीमों वाली डब्ल्यूपीएल में और टीमें जोड़ने की कोई तत्काल योजना नहीं है, लेकिन बर्मन वैश्विक स्तर पर इस खेल के विकास को लेकर आशान्वित हैं और इसलिए महिला लीग से भी जुड़ना चाहते हैं। पंजाब किंग्स में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले बर्मन ने पीटीआई से कहा, ''डब्ल्यूपीएल ने बहुत कम समय में ही महिला क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बना ली है। महिला क्रिकेट की प्रगति शानदार रही है। हमने शुरू में महिला

भारतीय मूल के आरोन राय ने तीन शॉट से पीजीए चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास

न्यूटाउन स्क्वायर : भारतीय मूल के ब्रिटिश गोल्फर आरोन राय ने अंतिम दौर में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए तीन शॉट से पीजीए चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास रच दिया। वह पिछली एक सदी से भी अधिक समय में इंग्लैंड में जन्मे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। राय पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर बनना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने गोल्फ को अपनाया। राय इस टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान पर थे लेकिन अब वह 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह 31 वर्षीय खिलाड़ी एक समय तीन शॉट से पीछे चल रहा था लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। राय ने पार-5 वाले नौवें होल पर 40 फुट का ईगल पुट लगाया। इसके बाद भी उन्होंने अपना अच्छा खेल जारी रखा और पांच अंडर 65 के स्कोर के साथ समापन

किया। उन्होंने कुल नौ अंडर का स्कोर बनाकर तीन शॉट से खिताब जीता। राय का इससे पहले किसी मेजर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तीन बार संयुक्त 19वें स्थान पर रहना था। उन्होंने अपने 13वें प्रयास में यह चैंपियनशिप जीती। वह पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले जिम बार्न्स ने 1916 और 1919 में यह खिताब जीता था। राय की जीत ने पीजीए चैंपियनशिप में अमेरिकी खिलाड़ियों की लगातार 10 वर्षों की जीत के सिलसिले को भी समाप्त कर दिया। राय के माता-पिता भारतीय मूल के हैं और उनकी पत्नी गौरिका भारत की एक पेशेवर गोल्फर हैं। राय से पहले पीजीए चैंपियन बनने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी विजय सिंह थे। फिजी के इस खिलाड़ी ने दो बार पीजीए चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने कहा, ''यह खिताब मेरी कल्पना से परे है।'' राय को इस जीत से पीजीए टूर पर पांच साल की छूट मिल गई है। अब वह मास्टर्स, यूएस ओपन और ब्रिटिश ओपन में खेल सकते हैं। वह अब जीवन भर पीजीए चैंपियनशिप में खेल सकते हैं। राय ने कहा, ''गोल्फ एक अद्भुत खेल है। यह आपको बहुत कुछ सिखाता है। यह आपको बहुत विनम्रता, अनुशासन और अथक परिश्रम करना सिखाता है क्योंकि इस खेल में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है।'' राय की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जॉन रहम, रोरी मैकलॉय, ज़ेंडर शॉफेल, कैमरन स्मिथ, जस्टिन रोज़ जैसे शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी में चैंपियनशिप जीती। रहम और एलेक्स स्माइली छह अंडर के कुल स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे।

ईशान और कमिंस ने सनराइजर्स को चेन्नई पर जीत दिलाकर प्लेआफ में पहुंचाया

चेन्नई : ईशान किशन के 70 रन और पैट कमिंस के तीन विकेट की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में प्लेआफ में जगह पक्की कर ली। जीत के लिये 181 रन का लक्ष्य चेपॉक की धीमी विकेट पर आसान नहीं था। ईशान ने हालांकि 47 गेंद की अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाकर इसे आसान बना दिया। हेनरिच क्लासेन ने 26 गेंद में 47 रन बनाये और दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 75 रन की साझेदारी करके हैदराबाद को 19 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन तक पहुंचाया। सनराइजर्स के अब 16 अंक है और उसे एक मैच और खेलना है। इस नतीजे के बाद गुजरात टाइटंस (16 अंक) भी प्लेआफ में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (18 अंक) पहले ही प्लेआफ में पहुंच चुकी है और अब बस एक स्थान के लिये मुकाबला है। चेन्नई के 13 मैचों में 12 अंक है और वह दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। मैच में सनराइजर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरूआत नहीं की और ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए। अभिषेक शर्मा भी 21 गेंद में 26 रन ही बना सके। पावरप्ले में स्कोर एक विकेट पर 45 रन था। क्लासेन को नूर अहमद की गेंद पर 18 के स्कोर पर स्पेंसर जॉनसन ने जीवनदान दिया। इसके बाद क्लासेन और ईशान ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। दोनों ने चेन्नई के स्पिनरों अकील हुसैन और नूर को सहजता से खेला। ईशान ने 37 गेंद में 50 रन पूरे किये। वहीं नूर की गेंद पर संजू सैमसन की कुशल स्टम्पिंग का शिकार होकर क्लासेन आउट हो गए। ईशान को अंशुल कम्बोज ने आउट किया लेकिन उस समय सनराइजर्स को जीत के लिये छह रन की ही जरूरत थी। इससे पहले कमिंस ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिये लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने सात विकेट पर 180 रन बना लिये। हैदराबाद के कप्तान कमिंस ने 28 रन देकर तीन विकेट चटकाये।इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। सैमसन ने टीम को शानदार शुरूआत देते हुए पहले ओवर में नीतिश कुमार रेड्डी को दो चौके और एक छक्का लगाकर 17 रन निकाले। प्रफुल्ल हिंसे को अगले ओवर में उन्होंने लगातार तीन चौके जड़े। कमिंस तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिये आये और सैमसन को विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों लपकवाया। उर्विल

अफगानिस्तान श्रृंखला के लिए भारतीय टीम: बुमराह के कार्यभार और रोहित की फिटनेस पर नजरें

गुवाहाटी : अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाली एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे मैचों की श्रृंखला के लिए मंगलवार को जब राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का चयन करेंगे, तब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन (खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए शारीरिक और मानसिक दबाव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया) और रोहित शर्मा की मैच फिटनेस पर विशेष चर्चा होगी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाना है, जबकि एक सप्ताह से भी कम समय के अंतराल पर छह जून से मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। वनडे मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में क्रमशः 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे। इस बात की संभावना कम है कि बुमराह को दोनों प्रारूपों के लिए चुना जाएगा, क्योंकि वनडे में उन्हें तुरंत खिलाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। 50 ओवर का विश्व कप अभी काफी दूर है (अक्टूबर-नवंबर 2027)। वहीं, रोहित शर्मा की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह मुंबई इंडियंस के कई मुकाबलों से बाहर रहे थे। पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में भी उन्होंने केवल 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में बल्लेबाजी की थी। ऐसे में चयनकर्ता उन्हें तभी टीम में शामिल करेंगे, जब वह पूरी तरह फिट होंगे। दूसरी ओर, विराट कोहली ने आईपीएल में शानदार फॉर्म दिखाकर अपनी उपयोगिता फिर साबित की है। रोहित की तरह अब केवल एक प्रारूप खेलने वाले कोहली के अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों वनडे मैचों में खेलने की पूरी संभावना है। सबसे अधिक महत्व एकमात्र टेस्ट मुकाबले को दिया जा रहा है, क्योंकि हाल के समय में भारतीय टीम पारंपरिक प्रारूप में, खासकर घरेलू परिस्थितियों में, संघर्ष करती नजर आई है। बल्लेबाजों की स्पिन-अनुकूल पिचों पर कमजोरियां लगातार सामने आई हैं।

एलएसजी के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में हर विभाग में सुधार करना होगा राजस्थान रॉयल्स को

जयपुर : राजस्थान रॉयल्स को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी धुंधली उम्मीदों को बरकरार रखना है तो उसे लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा। रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है और यहां होने वाला अंतिम मैच घरेलू टीम के लिए करो या मरो जैसा बन गया है। रॉयल्स इसके बाद लीग चरण के अपने अंतिम मैच में मुंबई इंडियंस का सामना करेगा। रॉयल्स को रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ निचले क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की खराब प्रदर्शन के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उसकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही थी। रॉयल्स की टीम अच्छी शुरुआत के लिए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर काफी हद तक निर्भर रही है, लेकिन इस युवा खिलाड़ी को दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है। ध्रुव जुरेल ने कुछ शानदार पारियां खेली हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने कुछ धीमी पारी खेली जबकि दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। कप्तान रियान पराग ने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह चाहेंगे कि उनकी टीम आखिरी पांच ओवरों में बल्लेबाजी में और अधिक सटीक प्रदर्शन करे।

भारतीय अंडर-18 हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर बराबर की श्रृंखला

भोपाल : भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम ने उधव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साइ (भारतीय खेल प्राधिकरण) केंद्र में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर चार मैचों की श्रृंखला में शानदार वापसी की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था, लेकिन रविवार को दूसरे मैच में 1-3 से हार गया था। भारत ने पहले हाफ में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आकाश दीप ने 10वें मिनट में पहला गोल किया, जिसके तुरंत बाद शाहरुख अली ने 14वें मिनट में दूसरा गोल दागा। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में दबाव बढ़ा दिया और केतन कुशवाहा (25वें मिनट) और रोमित पाल (26वें मिनट) ने लगातार गोल दागकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। कुशवाहा ने तीसरे क्वार्टर में अपना दूसरा गोल (40वें मिनट) किया, जिसके बाद अंश बहुड़ा (45वें मिनट) ने भारत की स्कोरिंग जारी रखी।

एशियाई खेलों के ट्रायल के लिये विनेश को राहत नहीं, दूसरा पक्ष सुनकर ही फैसला देगी अदालत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पहलवान विनेश फोगाट को 'दूसरे पक्ष की बात सुने बिना' तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। विनेश ने अदालत से 30 और 31 मई को एशियाई खेलों के लिये होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ ने उन्हें 26 जून तक डब्ल्यूएफआई के किसी भी टूर्नामेंट में भाग लेने से अयोग्य करार दिया है। अदालत ने विनेश को डब्ल्यूएफआई के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिये कहा है। महासंघ ने उस पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने महासंघ को निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस को छह जुलाई तक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाये और उनके समक्ष फैसला रखें। अदालत ने 'अयोग्यता' को लेकर विनेश की याचिका पर डब्ल्यूएफआई ,केंद्र और भारतीय ओलंपिक संघ को नोटिस दिये हैं और कहा कि इस मामले में 'प्रतिस्पर्धी हितों' के बीच संतुलन बनाये रखना जरूरी है। विनेश की ओर से सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने दिया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व अवकाश पर गई महिला एथलीटों की रैंकिंग और दर्जे को सुरक्षित रखा जाता है, वहीं डब्ल्यूएफआई की नवीनतम नीति ने उन्हें इससे बाहर रखा है। न्यायमूर्ति कौरव ने कहा, '' आपको पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हम दूसरे पक्ष को सुने बिना आपको वह राहत कैसे दे सकते हैं।

लिएंडर पेस की मां ओलंपियन जेनिफर पेस का निधन

नयी दिल्ली : भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान और ओलंपियन जेनिफर पेस का रविवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जेनिफर 72 वर्ष की थीं और वह भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस की मां थीं। परिवार के एक सूत्र ने बताया, ''वह कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित थीं और उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज कोलकाता के सेंट थॉमस चर्च में हुआ।'' उनका जन्म का नाम जेनिफर डटन था और वह प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त की वंशज थीं। उन्होंने वर्ष 1972 के म्यूनिख ओलंपिक 1972 में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और बाद में टीम की कप्तान भी बनीं। भारतीय महिला बास्केटबॉल में उन्हें प्रमुख हस्तियों में गिना जाता है। जेनिफर पेस एक प्रतिष्ठित खेल परिवार से जुड़ी थीं।

भारतीय शेयर बाजार विभिन्न झटकों को झेलने में सक्षम: सेबी चेयरमैन

भुवनेश्वर : बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार 'विभिन्न तरह के झटके झेल पाने' में सक्षम हैं। पांडेय ने यहां आयोजित 'क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता संगोष्ठी' के इतर संवाददाताओं से कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाले संकट का असर अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा, ''पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष से तेल आपूर्ति श्रृंखला और कीमतें प्रभावित हुई हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई का जोखिम बढ़ा है।'' उन्होंने कहा, इस स्थिति का असर सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है और आगे चलकर इसके प्रभाव का प्रसार और परवर्ती प्रभाव भी देखने को मिलेंगे।

देश को शोध एवं विकास पर निवेश बढ़ाकर जीडीपी का दो प्रतिशत करना चाहिए: रिपोर्ट

नयी दिल्ली : नीति आयोग ने सोमवार को कहा कि देश में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परिवेश को मजबूत करने के लिए भारत को अगले चार से पांच वर्षों में इस क्षेत्र में अपने निवेश को मौजूदा के 0.64 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम दो प्रतिशत करना चाहिए। आयोग ने 'ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया - रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, प्रमोटिंग एनेबलर्स' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा कि सरकार को आरएंडडी से जुड़ी खरीद पर पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब बहाल करने पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया, भारत के आरएंडडी परिवेश को मजबूत करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में राष्ट्रीय निवेश को मौजूदा 0.64 प्रतिशत से बढ़ाकर अगले चार से पांच साल में कम-से-कम जीडीपी के दो प्रतिशत तक ले जाने की तत्काल जरूरत है। नीति आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत को समयबद्ध और चरणबद्ध प्रोत्साहन देने की जरूरत है। नीति आयोग के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत अनुसूची-3 (बही-खाता एवं लाभ-हानि विवरण) में आरएंडडी व्यय के लिए अलग मद शामिल करने से निजी क्षेत्र के निवेश का बेहतर आकलन हो सकेगा और कंपनियां अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश के प्रति प्रोत्साहित होंगी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरएंडडी के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए अनुसंधान एवं विकास के लिए परमार्थ समर्थन आकर्षित करने के उद्देश्य से अधिक साहसिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसमें कहा गया, ''इसके लिए कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधानों को मजबूत करने और उनका प्रभावी उपयोग करने के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 133 के तहत आरएंडडी सहायता कोष में व्यक्तिगत योगदान पर अधिक कटौती (कम से कम 125 प्रतिशत) की सुविधा देने की आवश्यकता है।'' रिपोर्ट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक अंतर-विभागीय समिति गठित करने की भी सिफारिश की गई है, जो नियमित अंतराल पर बैठक कर विभिन्न विभागों एवं वित्तपोषण एजेंसियों की योजनाओं और पहल में समन्वय सुनिश्चित करे तथा योजनाओं की पुनरावृत्ति को कम करे। नीति आयोग ने कहा कि हालांकि कुल आवंटन राशि में वृद्धि हुई है, लेकिन जीडीपी के अनुपात में निवेश का स्तर अभी भी कम है।

कीमत बढ़ोतरी से पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा कम होकर 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन पर आया

नयी दिल्ली : पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) को होने वाले नुकसान में करीब एक-चौथाई की कमी आई है और यह घटकर लगभग 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मूल्य वृद्धि के पहले ओएमसी का दैनिक घाटा करीब 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। हालांकि, वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपये की कमजोरी के कारण खुदरा ईंधन दरें अब भी लागत से कम पर ही बनी हुई हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी देकर इसे घाटे की भरपाई करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि कंपनियों की 'अंडर-रिकवरी' यानी लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचने के कारण होने वाला घाटा अब भी करीब 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष की वजह से तेल आपूर्ति पर असर पड़ा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इस वजह से ओएमसी का घाटा बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया था। विश्लेषकों का कहना है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कंपनियों को सीमित राहत ही देगी और ऊंची कच्चे तेल की कीमतों के बीच कंपनियों की लाभप्रदता पूरी तरह बहाल नहीं कर पाएगी। डीबीएस बैंक की अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से मांग में कुछ कमी आ सकती है और आयात बोझ घट सकता है। उन्होंने अनुमान जताया कि इससे मुद्रास्फीति पर 0.15 से 0.25 प्रतिशत अंक का असर पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि उत्पाद शुल्क में राहत और हालिया बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा कम होकर करीब 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर रह गया है। हालांकि, पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से कुल नुकसान मई के अंत तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार गिरावट से उबरा, सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद

मुंबई : देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सोमवार को अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले कारोबार के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। भारी गिरावट के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और चुनिंदा प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी आने से बाजार की स्थिति सुधरी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और रुपये की कमजोरी ने बाजार की तेजी पर अंकुश लगाया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 77.05 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,315.04 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,134.78 अंक यानी 1.50 प्रतिशत तक टूटकर 74,180.26 अंक तक आ गया था। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक

सूचकांक निफ्टी 6.45 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 23,649.95 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी ओर टाटा स्टील, पावरग्रिड, भारतीय स्टेट बैंक और एनटीपीसी के शेयरों में गिरावट रही। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध बने रहने से बाजार की धारणा प्रभावित हो रही है। हालांकि, आईटी और बैंकिंग शेयरों में निचले स्तर पर खरीदारी आने से बाजार ने सत्र के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर ली।'' नायर ने कहा कि बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने, कच्चे तेल की कीमत में तेजी और कमजोर रुपया महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 54 पैसे कमजोर होकर 96.35 (अस्थायी) के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.17 प्रतिशत की बढ़त पर रहा जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप में 1.62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी प्रतिबंध छूट से इतर रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा भारत: अधिकारी

नयी दिल्ली : भारत ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट से इतर भी रूस से तेल खरीदता रहा है और आगे भी व्यावसायिक व्यवहार्यता तथा ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के आधार पर खरीद जारी रखेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, रूस पर अमेरिकी छूट के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम पहले भी रूस से तेल खरीदते रहे हैं... छूट से पहले भी, छूट के दौरान भी और अब भी खरीदते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के कच्चे तेल खरीदने के फैसले मुख्य रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण और पर्याप्त आपूर्ति उपलब्धता पर आधारित होते हैं। शर्मा ने कहा, हमारे लिए खरीदारी का आधार मूल रूप से व्यावसायिक समझ है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और दीर्घकालिक समझौतों के तहत पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। रूसी समुद्री मार्ग से कच्चे तेल की बिक्री और वितरण की अनुमति देने वाली अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी छूट 16 मई को समाप्त हो गई। यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने राहत उपाय की अवधि बढ़ाने पर स्पष्टता दिए बिना उसे समाप्त होने दिया। अमेरिकी वित्त विभाग ने यह सामान्य लाइसेंस पहली बार मार्च के मध्य में जारी किया था और अप्रैल में इसका विस्तार किया गया था। इसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़े दबाव को कम करना था। शर्मा ने कहा, छूट हो या नहीं, इससे उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्रेडिट कार्ड से लेनदेन चार साल में 2.6 गुना बढ़ा : आरबीआई रिपोर्ट

मुंबई : देश में कैलेंडर वर्ष 2021 से 2025 के बीच क्रेडिट कार्ड लेनदेन में 2.6 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरबीआई के अनुसार, इस अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए इस खंड में अपना दबदबा और मजबूत किया है। आरबीआई की 'भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2025' के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2021 में क्रेडिट कार्ड लेनदेन की संख्या 216 करोड़ थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 570 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान लेनदेन का मूल्य भी 8.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 23.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो करीब 27 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। इसके विपरीत, डेबिट कार्ड लेनदेन में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2021 में डेबिट कार्ड लेनदेन की संख्या 408.7 करोड़ थी, जो 2025 में घटकर 133.6 करोड़ रह गई। इस दौरान लेनदेन का मूल्य भी 7.4 लाख करोड़ रुपये से घटकर 4.5 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

अदाणी समूह ने अमेरिकी एजेंसी के साथ मामला निपटाया, 27.5 करोड़ डॉलर का किया भुगतान

नयी दिल्ली/ न्यूयॉर्क : अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लि. ने सोमवार को अमेरिकी वित्त विभाग के 'विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय' (ओएफएसी) को 27.5 करोड़ डॉलर का भुगतान कर ईरानी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के मामले का निपटारा कर लिया। यह मामला गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह के जरिये ईरान से जुड़े तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आयात से संबंधित है। कंपनी ने कहा कि उसने मामले की जांच में 'विस्तृत सहयोग' दिया और निष्कर्षों का 'स्वेच्छा से खुलासा' भी किया। अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी की अगुवाई वाली अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन से जुड़ी संभावित सिविल देनदारी के निपटारे के लिए 27.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि यह समझौता किसी प्रकार की दोषसिद्धि या गलत काम की पुष्टि नहीं करता और इससे संबंधित सभी देनदारियों का निपटारा कर देता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से वापस ले लिया है जिससे न्यूयॉर्क में चल रहा बहुचर्चित प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने अदालत में दाखिल दस्तावेज में कहा कि वे अब इन आरोपों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही अमेरिका में चल रहे अदाणी समूह से संबंधित सभी मामले पिछले कुछ दिनों में बंद किए जा चुके हैं।

वर्ष 11, पूर्णांक 3596 अंक 062 RNI No WBHIN/2016/66788, सर्वाग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सरोज राय द्वारा रजि. 17, बालमुकुन्द मक्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित।
सम्पादक- अनिल कुमार राय (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), कॉर्पोरेट आफिस : 230, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700 006, विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in